सर, जो प्रधान मंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को 'भारत रत्न' दिया है, मैं मानता हूं कि उससे दो बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की legacy को हम दोबारा institutionalise करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है, गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति-निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप study कीजिए, अपनी स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन, विचार और अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा, बड़ा काम 'भारत रत्न' देकर, जो भारत सरकार ने किया है, वह हौसला बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि यह एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। मैं जानता हूं कि आज की जो जीवंत समस्या और चुनौतियां देश के सामने हैं, किसानों की समस्याएं हैं, 'भारत रत्न' देकर उनका हल नहीं निकलता, लेकिन आने वाले सालों में झोंपड़ी में पैदा होने वाला व्यक्ति, जब वह कहेगा कि मुझ जैसा व्यक्ति चौधरी चरण सिंह बन सकता है, उनको 'भारत रत्न' मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। यह बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। चूंकि चौधरी साहब मेरे अकेले के नहीं हैं, एक पार्टी के नहीं हैं, मैं अपील करता हूं कि उनके लम्बे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में, जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, वे भी इस legacy का हिस्सा हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। वे वसीयत में कोई सम्पत्ति छोड़कर नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है, जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दलों के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। मैं फिर अपनी तरफ से ऋणी हूं और कहना चाहता हूं कि एक ज़मीनी सरकार, जो ज़मीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को 'भारत रत्न' दे सकती है, धन्यवाद।

---

## SHORT DURATION DISCUSSIONS

### White Paper on the Indian Economy and its impact on the lives of the people of the country

MR. CHAIRMAN: Short Duration Discussion. Notices have been received from the following Members to raise a discussion on the White Paper on the Indian Economy, laid on the Table of the Rajya Sabha on the 8th February, 2024, and its impact on the lives of the people of the country; Shri Sushil Kumar Modi, Shri Prakash Javadekar, Shri Brijlal. Now, Shri Sushil Kumar Modi. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, please give me one minute. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... Mr. Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: I will just take one minute. I wish to raise a point of order under Rule 33 and Rule 34 also says very clearly, 'The allocation of time in regard to the bill or group of bills or other business as recommended by the Committee, shall be reported by the Chairman or, in his absence, by the Deputy Chairman to the Council and notified in the Bulletin.' Sir, we have not received anything. We have not decided anything. The White Paper is very important. It is the prerogative of the Minister; the Minister may take one-and-a-half hours. But, for a party of 10 Members, we have been only given only six minutes. Who allotted the same? The BAC decides on the importance of the issue, on the importance of the Bill. We allot time, Sir. But, what time has been allotted and how was it allotted? The House was not informed about this.

MR. CHAIRMAN: Sukhendu Sekhar Ray*ji*. What is your point of order?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I am referring to Rule 29(2).

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: And, we are not disputing the authority of the Chair rather this rule empowers the Chair that any issue can be discussed with the permission of the Chair even if it is not listed in the List of Business. That is the rule. So, we accept that. This bickering, this exchange of heat could not have been there provided your Honour could have told, at the very beginning, that a communication was received from Shri Jayant Chaudhary...

MR. CHAIRMAN: That is over. I do not want to go back. मुझे बहुत दर्द हो रहा है।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: No, Sir. I am not... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Sukhendu Sekharji, I know you are a reasonable man. I have respects for you. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I am not creating any controversy. ...(*Interruptions*)...

**श्री सभापतिः** मैं उस बात को एक बुरे सपने की तरह भूलना चाहता हूं।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I am not creating any controversy. ...(*Interruptions*)...

**श्री सभापतिः** वह मेरे लिए एक बहुत भयानक सपना था।..(**व्यवधान**)..

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Please listen to me. We are not creating any controversy. ...(*Interruptions*)... सर, आप मुझे बोलने दीजिए। प्लीज़, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। महोदय, जिन्हें भारत रत्न दिये गये हैं, उनके लिए हम सभी के मन में, हमारी पार्टी के मन में श्रद्धा है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्री सुखेंदु शेखर रॉयः** हम इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। इसके लिए पहले ही बता देना चाहिए था कि यह इश्यू डिस्कस होना है। ...(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sushil Kumar Modi.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

**श्री सुशील कुमार मोदी** (बिहार): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला किया।

**डा. के. केशव राव** (तेलंगाना): इसके लिए क्या टाइम दिया है।...(**व्यवधान**)..पता नहीं है। ...(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Let him speak please. ...(*Interruptions*)... Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

**डा. के. केशव रावः** क्या टाइम दिया है।...(**व्यवधान**)..पता नहीं है। ...(**व्यवधान**)..

**श्री सुशील कुमार मोदीः** उपसभापति महोदय, पहले इनको बिठाइए। ...(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... The discussion has already started, Keshava Rao*ji*. Hon. Chairman has already said it. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*... Please speak. ...*(Interruptions)*... सुशील कुमार मोदी जी, आप बोलिए, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।.....(**व्यवधान**)..

**श्री सुशील कुमार मोदी:** उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला किया। ..(**व्यवधान**)..

SHRI TIRUCHI SIVA: We are not allowed to speak. What is this House for?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is Short Duration Discussion. It has already started, Mr. Tiruchi Siva. Hon. Chairman has already said it. Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

**श्री सुशील कुमार मोदी:** उपसभापति जी, इनको बिठाइए। ...(**व्यवधान**)..इस तरह से कैसे बोल पाएंगे?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...(*Interruptions*)... आप बोलिए।

**श्री सुशील कुमार मोदी:** उपसभापति जी, हाउस को ऑर्डर में लाइए। ...(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापति:** मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि ऑलरेडी यह डिस्कशन, Short Duration Discussion on White Paper शुरू हो चुका है। Please take your seat. ...(*Interruptions*)... माननीय चेयरमैन साहब ने बताया है कि यह डिस्कशन शुरू हो चुका है, सैंक्शन्ड है। He has already explained it. माननीय सुशील कुमार मोदी जी, आप बोलिए।

**श्री सुशील कुमार मोदी:** उपसभापति महोदय, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह केवल 27 दिनों के लिए देश के प्रधान मंत्री रह पाए। कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन विश्वास मत हासिल करने से पहले कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। फिर चौधरी चरण सिंह जी संसद का मुंह नहीं देख पाए। उसी प्रकार श्री पी.वी. नरसिम्हा राव...

**श्री उपसभापति:** माननीय मोदी जी, आप व्हाइट पेपर पर बोल रहे हैं।

**श्री सुशील कुमार मोदी:** मैं उसी पर बोल रहा हूं।

**श्री उपसभापतिः** जी, बोलें।

**श्री सुशील कुमार मोदीः** श्री पी. वी. नरसिम्हा राव, जो आर्थिक सुधार के जनक हैं, जिन्होंने 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, उन नरसिम्हा राव जी के शरीर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। नरसिम्हा राव जी का दाह संस्कार आंध्र में किया गया। उनका स्मारक बनाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। उनका स्मारक नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में बनाने का काम किया। जो नरसिम्हा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, उन रिफॉर्म्स को आगे ले जाने में कांग्रेस के लोग श्री नरसिम्हा राव को भूल गए।

उपसभापति महोदय, 2014 में जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, उस समय देश की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, पब्लिक फाइनेंस बुरी अवस्था में था, आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता थी, अत्यधिक संकट की स्थिति थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, banking crisis was massive and stake was too large. There have been policy paralysis and project delays. नीतियों की अनिश्चितता और विरोध के कारण घरेलू निवेशक विदेशों में जाने लगे। The decade of UPA was a lost decade. उस समय नेतृत्व का संकट था, अर्थव्यवस्था रास्ता भटक चुकी थी, आर्थिक कुप्रबंधन ने भारत के विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया और भारत एक फ्रेज़ाइल इकोनॉमी बन गया। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यूपीए के जो 10 साल थे, that was the most corrupt regime which this country has ever seen. मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में उनके 7 मंत्री जेल गए। श्री ए. राजा, श्री दयानिधि मारन, श्री सुरेश कलमाड़ी, श्री पवन कुमार बंसल, अश्वनी कुमार, वीरभद्र सिंह, अशोक चव्हाण, ये 7 लोग यूपीए सरकार में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और जेल जाना पड़ा। श्री ए. राजा 15 महीने जेल में रहे। सुरेश कलमाड़ी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑर्गनाइज़िंग कमेटी के चेयरमैन थे, वे 10 महीने तिहाड़ जेल में रहे। अशोक चव्हाण ने, जो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में - कारगिल की वॉर विडोज़ के लिए जो फ्लैट्स बने थे, उनको सिविलियन्स को देने का काम किया। दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन 2जी स्कैम के अभियुक्त थे। उनको भी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। श्री पी.के. बंसल को रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनका भगिना विजय सिंगला 90 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लॉ मिनिस्टर अश्वनी कुमार को भी इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वे कोल ब्लॉक स्कैम में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। डा. वीरभद्र सिंह जो एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर थे, हिमाचल प्रदेश में विजिलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ और उनको इस्तीफा देना पड़ा। श्री शशि थरूर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे, आईपीएल टीम कोच्चि के विवाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। उपसभापति महोदय, यह थी यूपीए की सरकार, जिनके 7 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जेल जाना पड़ा या इस्तीफा देना पड़ा।

उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए, लेकिन एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, प्रधान मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। राफेल का मुद्दा उठा, अडाणी का मुद्दा उठा, कहा कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी माँगनी पड़ी। NDA की सरकार 10 साल से सरकार में है! नरेन्द्र मोदी जी लंबे

समय तक गुजरात के मुख्य मंत्री थे, उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। दूसरी ओर यूपीए की सरकार! उपसभापति महोदय, कोल ब्लॉक आवंटन में इन्होंने नियम बना दिया - "पहले आओ, पहले पाओ"। ऐसा भी कोई नियम है दुनिया में कि जो पहले आएगा, उसको कोयले का कैप्टिव माइंस मिल जाएगा। सीएजी के अनुसार 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसे आवंटन को रद्द कर दिया। 47 मामलों में फाइनल रिपोर्ट सब्मिट हो गई, 14 में अभियुक्तों को सजा हुई है। दूसरी ओर जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तो कोयले का ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन हो रहा है। कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, आजादी के बाद 893 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 2014 की तुलना में उत्पादन में 57.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उपसभापति महोदय, कोयले के कारण जो भारत पावर डिफिशिएंट था, India has become a power sufficient country. 2014 के बाद 1,96,000 मेगावॉट जेनरेशन कैपेसिटी का इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पहले 12 घंटे बिजली मिलती थी, अब 20 घंटे बिजली मिल रही है और अर्बन क्षेत्रों में 23.8 घंटे बिजली मिल रही है।

उपसभापति महोदय, 2जी स्कैम कौन नहीं जानता है! 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस है, वह 1,76,000 करोड़ है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take you seats. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. आप बोलें।

**श्री सुशील कुमार मोदी:** उपसभापति महोदय, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन पारदर्शी तरीके से हुआ है। 5जी को दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तरीके से भारत में रोल आऊट किया गया। आज देश के 98 परसेंट गाँवों में 4जी पहुँच चुका है। उपसभापति महोदय, जहाँ यूपीए के जमाने में 2जी स्कैम हुआ, वहाँ 5जी के कारण सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 3 लाख करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, 5जी के स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार को 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। उपसभापति महोदय, UPA decade was a lost decade for telecom. इन लोगों ने बीएसएनल को बरबाद कर दिया। बीएसएनएल, जो 2004 में 6 बिलियन डॉलर की कंपनी थी, 2014 में वह लॉस मेकिंग कंपनी में बदल गई। जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तो हमारी सरकार ने बीएसएनल को रिवाइव करने के लिए 3.22 लाख करोड़, तीन पैकेज के माध्यम से देने का काम किया। आज बीएसएनल का रिवाइवल हो चुका है।

उपसभापति महोदय, कॉमनवेल्थ गेम्स 12 दिन का गेम था, जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। भारत में जी20 हुआ, 1,300 करोड़ खर्च हुआ, पूरे देश में कार्यक्रम हुआ, लेकिन कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उपसभापति महोदय, हेलिकॉप्टर खरीद में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट परचेज घोटाला, पाइलेटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला, नौकरी में रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम। हिन्दुस्तान में आजादी के बाद अगर कोई सबसे भ्रष्ट सरकार थी, तो यूपीए की सरकार थी। उपसभापति महोदय, बैंकों को इन लोगों ने बरबाद कर दिया। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में पदमुक्त हुए, तो उस समय वे एक अच्छी अर्थव्यवस्था सौंप कर गये थे।

महोदय, सितम्बर, 2013 में यूपीए सरकार में एनपीए 12.3 परसेंट पहुँच गया था और कमर्शियल लेंडिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा। मार्च, 2004 में जहाँ ग्रॉस एडवांस 6.6 लाख करोड़ था, वह 8 साल में बढ़ कर 39 लाख करोड़ हो गया। यानी बैंकों का लोन 6.6 लाख करोड़ से बढ़ कर 39 लाख करोड़ हो गया। बैंकों को फोन पर निर्देश जाते थे कि फलां उद्योगपति को कर्जा दे दो और बैंक फोन बैंकिंग की बदौलत कर्जा दिया करते थे। आज क्या स्थिति है? 2023 में जीएनपीए 4.4 परसेंट है, नेट एनपीए केवल 1 परसेंट है। आज बैंकों का स्वर्ण युग है। This is the golden era of banking. आज सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स फायदे में हैं। 2022-23 में बैंकों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। बैंकों को अगर आज फायदा हुआ है, तो उसमें भारत सरकार ने recapitalize करने के लिए बैंकों को 5 साल में 3.10 लाख करोड़ रुपये देने का काम किया है।

महोदय, इन लोगों को आर्थिक सुधार करने का मौका मिला। नरसिम्हा राव जी का नाम लेते हैं, लेकिन 2004 के बाद एक भी आर्थिक सुधार इन लोगों ने नहीं किया। जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तो हमने इस देश में जीएसटी लागू किया। सभी राज्यों को लेकर जीएसटी लागू किया। आपने तो घोषणा की थी कि 2010 में जीएसटी लागू करेंगे। मैं कांग्रेस के लोगों से, यूपीए के लोगों से जानना चाहता हूँ कि वे 2010 में जीएसटी क्यों नहीं लागू कर पाए? जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तो 2017 में इस देश के अन्दर जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी के कारण दिसम्बर, 2017 से लेकर मार्च, 2023 तक प्रति माह 45,000 करोड़ की बचत परिवारों को हुई है।

महोदय, 2004 की स्थिति क्या थी और आज 2024 में क्या स्थिति है - आज inflation नियंत्रण में है, विकास दर 7 परसेंट से ज्यादा है, जो दुनिया की सर्वाधिक विकास दर है। हमारे पास रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है, 620 बिलियन यूएस डॉलर का रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है। पहले हम fragile five economies में थे, आज हम top 5 economies में हैं। लोगों का जो भरोसा खत्म हो गया था, एक बार फिर से लोगों का भरोसा सरकार में पैदा हुआ है। हम लोगों ने कोविड का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। हम लोगों ने सरकारी योजनाओं में छिट-पुट लाभ नहीं, बल्कि saturate करने का काम किया। आज हम digital payments में वर्ल्ड लीडर हैं, हमने डिजिटल क्रांति की है। हमने देश को खुले में शौच से मुक्त किया है। देश में Made in India कोविड का टीका बनाकर पूरी आबादी का टीकाकरण किया है। आज की हमारी ये उपलब्धियाँ देश के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।

महोदय, 2004 और अब - तब और अब में क्या फर्क है? तब इंफ्लेशन 8.2 परसेंट था, आज यह 5 परसेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट उस समय 7.6 बिलियन डॉलर था और आज ...(**व्यवधान**)... थोड़ा शान्त रहिए। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट 7.6 बिलियन डॉलर था, आज यह 22.7 बिलियन डॉलर है। एफडीआई तब 305 बिलियन यूएस डॉलर था, आज 596 बिलियन यूएस डॉलर है। तब स्टार्टअप्स की संख्या 350 थी और आज उसकी संख्या 1,17,257 है। मेट्रो रेल तब, यानी 2014 में 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में मेट्रो चल रही है।

महोदय, उनके 10 साल में 25 हजार किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ और नरेन्द्र मोदी जी के 10 साल में 55 हजार किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ। उनके कार्य काल में एनएच निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी और नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में it has increased from 12 kilometres to 29 kilometres per day. रेल दुर्घटना उनके समय में 233 हुई थीं और नरेन्द्र मोदी जी के समय में, it has decreased from 233 to only 34. रेल का

electrification उनके जमाने में 22 हजार किलोमीटर हुआ था और हमारे 10 साल में 60 हजार किलोमीटर electrification हुआ है। उनके समय में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी और आज यह संख्या 149 है।

महोदय, उनके समय में टोल प्लाज़ा पर 12 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था और आज टोल प्लाज़ा पर केवल 47 सेकंड इंतजार करना पड़ता है। उनके समय में मोबाइल ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स की संख्या 6 करोड़ थी और आज नरेन्द्र मोदी जी के समय में, 2024 में वह 90 करोड़ है।...(**समय की घंटी**)... सर, दो मिनट और।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. आपकी पार्टी के समय से यह समय जाएगा।

**श्री सुशील कुमार मोदीः** सर, एक मिनट और। उनके समय में मंथली डेटा का consumption 0.06 जीबी प्रति माह था और हमारे समय में 22 जीबी डेटा प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है। आपके समय में डेटा का टैरिफ 270 रुपए प्रति जीबी था और आज वह 10 रुपए प्रति जीबी है। उनके समय में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और आज उसकी संख्या 706 है। उनके समय में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 51 हजार थी और आज उसकी संख्या 1,08,000 है। उनके समय में number of universities 676 थीं और आज उसकी संख्या 1,168 है।

महोदय, उनके समय में number of LPG connections 14 करोड़ थे और आज उसकी संख्या 31 करोड़ है। उनके समय में number of PNG connections 22 लाख थे और आज उसकी संख्या 1 करोड़ 19 लाख है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली 12 घंटे थी और आज वहाँ 20 घंटे से ज्यादा बिजली है। उनके समय में number of tap water connections 3.2 करोड़ थे और आज उसकी संख्या 13.8 करोड़ है। उनके समय में total number of DBT beneficiaries 10 करोड़ थे और आज उसकी संख्या 166 करोड़ है।

महोदय, अंत में, मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुँचे हैं, तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और हम तूफान से किश्ती को निकाल कर लाए हैं।...(**समय की घंटी**)... महोदय, हम विश्वास प्रकट करते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, धन्यवाद।

**श्री उपसभापतिः** धन्यवाद, सुशील कुमार मोदी जी। के. सी. वेणुगोपाल जी, मैं आपको आमंत्रित करूँ, उसके पहले आप सबकी अनुमति चाहूँगा, क्योंकि एच. डी. देवेगौड़ा जी दो मिनट कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आपकी सहमति हो, तो मैं पहले उनको यह अवसर दूँ। माननीय देवेगौड़ा जी, please speak.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for the kind expression made by our hon. Member. Sir, I thought that the House was going to be closed on 9th February because earlier the Parliament Session was scheduled to be till 9th February. But, it was extended till 10th February. I have to attend a marriage function in my family relation today evening. I must catch the flight.

There is no flight available, if I miss this flight. That is why I had made this request to the hon. Chairman.

Sir, on the White Paper issue, hon. Finance Minister is sitting here. Yesterday what she answered in the Lok Sabha to the issues raised by our other friends on, what they call, 'Black Paper', I heard every word.

12.00 P.M.

I cannot sit in the House for four hours; you know my health condition. I sat in our House, I heard every word of your answers on all the points. You are so strong and your voice is so strong, you hit back all the Opposition people who tried to criticize. I know your capacity, Madam, and I do not want to speak on the White Paper because the White Paper is with me. I have gone through that. On Budget proposals I wanted to speak. Unfortunately, when the Chairman called me, I was not here; I was unable to participate.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

Now, the issue which is again going to be discussed in the Lok Sabha the whole day is the Ram Temple issue. The Prime Minister is going to answer in the evening, according to the information I have got from the Lok Sabha. Now, I do not want to go beyond some of the points which have been discussed here on this so-called the Bharat Ratna issue. Sir, I became a Member of the Legislative Assembly at the age of 31. I was associated with Chaudhary Charan Singh for four years. I myself, with my family, stayed in his house. He used to like me so much because I am a farmer. I was unable to speak Hindi, my wife was also unable to speak Hindi, but he made me stay in his house. I have got so much of relationship. What has happened, I know. He had taken oath as the Prime Minister, he was not able to come to this House. When the agenda was fixed to meet in the Lok Sabha, the previous day, it was withdrawn. It was such a sorrowful day for me; I know Chaudhary Charan Singh. He was honest to the core. How people tried to demolish his name, I know everything. I do not want to go beyond that. The book he has written, referred by my young gentleman, I know. I have gone through that book. I have got that book. I can speak volumes. He was unable to come and sit in this House as Prime Minister. Late Sanjeeva Reddy asked him to conduct the elections. I can speak volumes on so many issues. The progress of this country during the period of ten years - yesterday, Madam replied sufficiently to meet the charges made by our other colleagues on 'Black Paper'. I would leave it

at that stage. Sir, Dr. Swaminathan — for the first time, I met him in Phillipines in 1974. I know what was Dr. Swaminathan. For about 10 months, I also took his service on Green Revolution. On Shri P.V. Narasimha Rao, I can speak volumes. I do not want to go beyond that. Only on the Ram Temple, I will conclude in four, five minutes. Sir, just because I do not want to go on speaking unnecessarily, I may not be able to speak eloquent English, that is why I have made it. Sir, I and my wife both attended the consecration of the Lord Rama Temple in Ayodhya. It was a great moment of personal joy and devotion for me like it was to millions of Indians. Lord Ram who has existed in our hearts and minds is an image that our ancestors and elders have permanently created. Lord Rama is a symbol of righteousness. He is a symbol of love and graciousness. He is a man who followed dharma and rajadharma. He was very accommodative and reflective. It is these values enshrined in Lord Rama that drew Mahatma Gandhi to him. It was Gandhiji who made Lord Rama the symbol of great virtues for our nation. It is through Lord Rama and his divine blessings that he united this nation and laid the foundations for our harmonious future. It is through the moral strength that Lord Rama gave that he fought the British Empire. I sincerely wish and pray to Lord Rama whom our ancestors and elders have given us and the new Rama Temple in Ayodhya becomes a symbol of great humanity for our nation and the world.

Sir, lastly, I congratulate the hon. Prime Minister who, when Rama statue was being installed, for ten days, had a *vrat* taking only juice and water. He is such a person who actually performed that function. I was so happy and I must be very frank, not to please the Prime Minister, but he was so dedicated and sincere in performing that function with *pundits*. I was there.

Sir, about Chaudhary Charan Singh or Shri Narasimha Rao or Dr. Swaminathan, volumes become speech. To such people, he conferred the *Bharat Ratna*. The House should enjoy it. The country should welcome it. The country is going to welcome it. Let us not unnecessarily try to differ on it. Again we should differ from each other on major issues taken by the Prime Minister but we should not differ on issues like conferring *Bharat Ratna* to these great three leaders. Thank you. You have given me some time. I am grateful to you.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Thank you former Prime Minister.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Thanks to all the Members who allowed me to speak when you called the other Member. I am grateful to you. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Shri K.C. Venugopal.

SHRI K.C. VENUGOPAL (Rajasthan): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to discuss about the so-called White Paper presented in this august House.

Basically, Madam, this is not the White Paper, the White Paper which totally hides the dark truth of your economic situation in this country. Every individual in any way is related to economy. When we buy some commodities in the market, it is related to our economy. When we buy a car and use petrol, it is related to the economy. When a person takes a bank loan and pays interest to the bank, he is related to the economy. People from every walk of life are related to the economy. Therefore, it is very much important to discuss the economy of this country. You are introducing a White Paper about the condition of the economy during UPA's regime from 2004 to 2014, or from 2014 to 2024, the words used are -- I am quoting the 'objectives of the White Paper' -- "It seeks to apprise hon. Members of Parliament and people of India of the nature and extent of the Government's economic and fiscal crisis that was bequeathed on this Government when it assumed office in 2014." What was the fiscal situation particularly in 2014? The GDP growth was the highest in 2014. You have said that it was very shocking for you. I don't understand that at all. Basically, if you take the average GDP growth during the UPA era and the NDA era, it was more than 7.6 per cent during the UPA regime, but now it is only 5 per cent. How can it be like that? When you are producing a White Paper and talking about your period also, two-three major issues should have been reflected in that, which is totally missing. One is the demonetization, the so-called 'demonetization'. I searched the White Paper thoroughly; there is not a single word about demonetization. Why is that so? I recall the speech that the hon. Prime Minister made in Goa immediately after demonetization. He said that all the black money of the country would be brought out and all the fake currency that is circulating in the economic system is going to be taken out. Why don't you talk about that statistics? How much black money have you brought back? You said that terrorism would be wiped out. That statistics must be presented. When you are introducing a White Paper, we need to know those statistics. The then Prime Minister, who was in office from 2004 to 2014, Dr. Manmohan Singh, said, "It is a legalized loot and organized plunder." That has been proved now. He predicted then that there would be an impact of two per cent on the GDP. That has actually happened. You could have made a mention about the impact of demonetization in your White Paper. What is the situation of the MSME sector now? The small and medium sector is totally destroyed now. That is why unemployment is at its peak now, because major employment is given by the MSME only. That sector has already vanished. Then, I also searched whether the White

Paper gave any information about the unemployment rate. What about the situation of unemployment? When Dr. Manmohan Singh completed eight years in April, 2012, at that time, unemployment rate of the country was 5.6 per cent. In comparison, the data, after completion of eight years of the Narendra Modi Government in 2022, is not clear. We have the Right to Information Act, but no information is coming out. We have information that in 2022, unemployment rate was 8 per cent. It was 5.6 per cent earlier but eight per cent now. Which figure is lower, Sir? Why don't you talk about unemployment in this country in this White Paper? The entire youth of this country is eagerly waiting for that only. When are they going to get employment? Why is there this situation of the youth now? There is no answer for this. If there is an answer, there is no mention here. Then, there is no information about poverty here. When UPA was in power, we brought 27 per cent people above the poverty line. But you have brought 23 per cent people below poverty. Yesterday, my friend, Tiruchi Siva, already quoted global rating in the Hunger Index. We are at the 11$^{th}$ position. There is no mention about it. When Dr. Manmohan Singh was in power, there was devaluation of rupee, and the then Chief Minister of Gujarat himself said, "Our Rupee is on ventilator." Yes, during Dr. Manmohan Singh's period also, there was global economic crisis and the rupee devalued 22 per cent. Now, the devaluation is around 32 per cent. Where is the rupee now, Madam, if at that time, it was on ventilator, where is it now? Nothing is there in the White Paper. Chaudhary Charan Singh was the stalwart of this country. Narasimha Rao was the Prime Minister of this country. At that time, our economy was in great danger when he took over as the Prime Minister. He made drastic changes through Dr. Manmohan Singh who was the Finance Minister at that time. Of course, I am elected from Alleppey where Dr. M.S. Swaminathan is known as 'Mankombu', which is also a village in Alleppey. He was the great warrior of this country. Since we are in a situation of food security now, we have to remember Swaminathan*ji*. Who gave maximum opportunity to Swaminathan*ji*? Who made him the Chairman of Indian Council of Agriculture Research? Who made him the nominated Member of this august House? He deserves more than it. We gave him Padma Vibhushan. We are very happy if *Bharat Ratna* is given to all these people. We are not against Chaudhary Charan Singh. Who made Chaudhary Charan Singh Prime Minister? Don't dispute it. You have chosen him only for political purpose, but the Congress has never used his name for political purpose. That is the only difference between us. You are using *Bharat Ratna* for elections. Why didn't you give it last year? Why did you wait for ten years? Why are you discussing it on the last day today? Our Session was concluding yesterday. ...*(Interruptions)*... Actually, this White Paper is the paper which is hiding the dark

truths. I heard the hon. Prime Minister's speech in this House. He spoke for one-and-a-half hours. Out of that one-and-a-half hour, for the maximum time, he attacked the Congress Party. He talked about Modi's guarantee. I saw his speeches in Kerala also where he talked about Modi's guarantee. I am very happy that you are using the word 'guarantee'. When we used the word 'guarantee' in Karnataka, you people told that there is no meaning of 'guarantee' in this world. When we used the word 'guarantee' in Karnataka, what was the comment and reaction? Pralhad Joshi*ji* is here. ...*(Interruptions)*... Now, the 'guarantee' is approved. Everywhere the Prime Minister is telling 'Modi's guarantee'. ...*(Interruptions)*... When we are giving new guarantee, we have to think about the guarantee which had been given by your Prime Minister to the country -- two crore jobs per year. That guarantee was given by the hon. Prime Minister. Ten years are over. How many jobs have you given? Another guarantee was bringing back the black money stashed abroad within 100 days. What happened to that? Then, it was guaranteed that Rs.15 lakh would be given to every citizen in his bank account. What happened? It was also guaranteed that farmers' income would be doubled. But, what has happened? Another guarantee was to achieve the economy size of $5 trillion by 2023-24. What happened to that? Then, 100 smart cities were guaranteed by 2022. Therefore, when you are taking about the guarantees for future, at least, do a post-mortem as to what happened to each of the guarantees you had given to the country in the past. Nothing has happened. My point is that the most important thing in a person's life is to be able to live happy and healthy as long as possible. I was going through the data relating to life expectancy in our country at present. The World Bank's data is there in this regard.

MR. CHAIRMAN: Tell me, I am keen to know. I am 70.

SHRI K.C. VENUGOPAL: A child born when Vajpayeeji was the Prime Minister could expect a life of 64 years. A child born when Manmohan Singhji was the Prime Minister could expect a life of 69 years; an increase of five years in life expectancy. But, now, what is the status? A child born when Narendra Modiji is the Prime Minister can expect to live only for 67 years. That is two years below as compared to the life expectancy during Manmohan Singhji's regime. There is a reason for this.

MR. CHAIRMAN: Where do you get it from?

SHRI K.C. VENUGOPAL: It is World Bank's data. This has happened because the expenditure on health sector has not increased in this ten-year period. What is the

reason? In the UPA Government, 1.7 per cent was the expenditure on Health Department. We have the same situation today also. Even after 10 years, we are spending 1.7 per cent only on the health sector, even after Covid happened and maximum health issues happened in this country. Even after all these things, there has been no increase in the health budget. That is why, the life expectancy is coming down.

Now, I come to the education sector. In 2004, when the UPA came to power, the expenditure on education was 2.2 per cent. But the UPA Government increased it drastically and it was more than doubled. It was 4.6 per cent in 2014 when the UPA left the Office. But, what has this Government done? This Government has slashed it down to 2.9 per cent. From 4.6 per cent in 2014, it has been brought down to 2.9 per cent now. They are talking about '*Beti Bachao, Beti Padhao*'. But, what is the situation? If we look at the female literacy rate -- you can see the statistics also -- when the UPA was in power, rate of increase in female literacy rate was 1.3 per cent. Now, there is an increase of only 0.6 per cent in female literacy rate. They can verify this.

When we talk about the major impact, I would like to highlight that Manmohan Singh Government had spent 16 per cent on subsidies for the poor people. This Government has cut down the subsidies for the poor people from 16 per cent to 9 per cent. That is why, India had gained 9.4 percentage points in the Human Development Index during the UPA period. Now, it has come to 0.4 per cent, which is very low. All these things are leading to a clear fact that during the UPA period, we had done a much better job in managing the deficits. The Modi Government boasts very much and does a lot of PR work. Every day, they are giving huge advertisements using public exchequer. Propaganda mechanism and decorative words are there but you have to understand that the country's financial situation is bad due to the bad financial management. I am talking about the situation of poor people and their living conditions. Poor are becoming poorer and rich are becoming richer. The gap between the poor and the rich is increasing. You are only interested in the corporate world.

Madam, Annexure-2 boasts that India's average per capita GDP has increased roughly from US $ 4,000 to US $6,000. Very cleverly, you have used the words, average per capita GDP. Sir, average per capita GDP will, certainly, increase in a developing country like India. But there is unsaid truth. Annual average per capita GDP growth fell from 5.9 per cent during Manmohan Singh's tenure to 3.8 per cent during Modi's tenure. In other words, the average Indian people income grew much faster during the period when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister than

during the tenure of Narendra Modi. It is a clear fact but you are hiding it. You are using the facts only for your benefit.

Let me mention about foreign investment. There is a big boost in the foreign investment in the White Paper but what is the real situation? The fact is that net foreign investment was 1.2 per cent of GDP in the UPA regime while it is 0.8 per cent of GDP in the NDA regime. During UPA's period, it was 1.2 per cent and during your period, it is 0.8 per cent. Foreign reserves nearly tripled and exports were 17 per cent of the GDP when UPA was in power against 14 per cent during NDA rule. Simply put, foreign investors and consumers gushed over India's economy and products far more during the tenure of silent and estimable Manmohan Singh ji than during the loud and bombastic Modi ji's period. You use the decorative words but Manmohan Singh ji did it silently. That was the golden period for private investment. It is the situation. Manufacturers were also more confident in that period. Data shows this, Sir. Not only private corporate houses but farmers also did not show confidence in Modi's tenure. We are talking about big things for farmers. Growth in foodgrains production fell from 34 per cent during UPA regime to 31 per cent in your period. From 34 per cent to 31 per cent! It is not even the case that domestic stock markets loved Modi's tenure. ...(*Time-bell rings.*)...I am only talking about the economy; nothing else. The BSE sensex grew 13.4 per cent annually during UPA regime versus 8.2 per cent during NDA regime.

Sir, the job market is depressing, especially for the youth. The Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) report shows that the unemployment rate in age group 20 to 24 years, the crucial period, was 44.5 per cent. Sir, 44.5 per cent of youth in the age group of 20 to 24 are unemployed! In the October-December, 2023 statistics, for the age group of 25-29 years, it was at 14 months high of 14.33 per cent. Sir, this is the real situation which the country is facing today.

You have brought White Paper to abuse UPA Government. Can I ask a question? ...(*Time-bell rings.*)... I am concluding, Sir. During the UPA regime from 2004 to 2014, we brought Right to Education, we brought Right to Employment, we brought Right to Information, we brought Right to Food. Can Nirmala ji enlighten us which is the flagship programme of the Narendra Modi Government like MNREGA in this country, which is a game-changer? Our Prime Minister said that his can be kept as a memory. Then he changed later. Sir, the UPA period, from 2004-2014, was actually a game-changer. MNREGA, Right to Information, Right to Food, everything was brought during that period. (*Time-bell rings.*) You want to take it as your period. Somebody was talking about corruption. If you are very much sincere about corruption, why are you scared of the CAG Report of your Government? That is

revealing the clear corruption in the Government. You talk about the CAG Report of the UPA Government and saying that our Government was corrupt. But you don't want to reveal the CAG Report of your Government. Therefore, this is actually not a White Paper, but this is a Paper which is hiding the entire dark truth of this country.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI K.C. VENUGOPAL: These people are ruining the country. Our youth are completely disappointed. Our farmers are completely disappointed. They are marching to Parliament every day. They are in a very distressed situation. Sir, everybody is unhappy with this Government. They just want to divert the attention from the situation of this country; they want to divert the attention from the unemployment situation of this country; they want to divert the attention from the price rise situation of this country; they want to divert the attention to some other way. Actually, this White Paper is going to be a total defensive paper for the Government. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Saket Gokhale.

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): Thank you very much, Sir. Today is my maiden speech in this august House and I wish to thank my leaders, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee and my party, Trinamool Congress for giving me this opportunity.

MR. CHAIRMAN: Mr. Saket Gokhle, you have eight minutes. Is it your maiden speech?

SHRI SAKET GOKHALE : Yes, Sir. It is my maiden speech.

MR. CHAIRMAN: We will make it ten minutes.

SHRI SAKET GOKHALE: Thank you, Sir. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: I understand. He agrees. He is a reasonable Member. I know he is very sharp, very intelligent. He will monetize every second of it.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I want to start with a short story today by the famous Danish writer, Hans Christien Andersen.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

The story goes that there was once a very famous emperor who was extremely self-obsessed with himself and his clothes. He had no interest in his kingdom or in the welfare of his people. All that the emperor did every day was, sit in his wardrobe while the Ministers around him kept telling him how beautiful his clothes were and how great he was. One day, two cheats came to his kingdom, pretending to be tailors, and offered to make new clothes for the emperor, because he loved new clothes. The tailors promised to make an exquisite suit for the king with special properties. The new suit, they said, would be the finest cloth that the emperor had ever worn. But there was one special feature. They said that the suit was only for the great emperor and the suit would be invisible to anybody who is a dishonest person. Several Ministers of the emperor went to the fake tailors while they were making the suit. The Ministers, obviously, could not see the suit. But they blamed themselves for that because they were afraid that they might be branded dishonest if they could not see the suit. On the day of the great procession, the emperor went on to try the new clothes. He himself could not see those clothes but, obviously, he did not want to claim that he was dishonest. So, he went along with it. The emperor then put on his new suit and started a procession through the city. People across the kingdom had heard about the emperor's new clothes which were so special that they would be visible only to those who were honest. So, out of fear, the people started screaming, "Oh, so beautiful clothes, so lovely clothes", because nobody wanted to be seen as dishonest or anti-national. Then, suddenly, one innocent child screamed from the audience, "What is wrong with all of you? The emperor is naked." This is precisely what the claims in this White Paper on the economy are. They are the emperor's invisible clothes. My hon. Minister's colleagues here will spend hours talking about how beautiful these invisible clothes of a great emperor are. But the truth of our economy as shown in this White Paper is that the emperor is naked. But we all have to admit one thing. This White Paper is magical. It is magical because after reading this White Paper, I realise that something called demonetisation never happened! I remember, a few years ago, the Prime Minister showed upon our TV screens one fine evening and said that in the next two-three hours, 60-70 per cent of our currency will be demonetized. I remember what my leader, Mamata Banerjee, said at that point of time. She is not an economist, but she is connected with the hardships of the people

on the ground. She said that demonetization will be a disaster. And that proved to be right. People scrambled to ATMs for cash. People queued up for hours. Hundreds of people died. ATMs had not even been configured for the new notes. They had to recalibrate all the ATMs in the country. That is how disastrously planned this move was. Then the Prime Minister came up with a genius idea that I will scrap Rs.1,000 notes, but I will bring in Rs.2,000 notes. The idea was that people are stuffing money in the mattresses, so let me demonetise Rs.1,000 notes and let me make it easier for them by bringing Rs.2,000 notes. Only Prime Minister Modi has that kind of vision and genius. After that, the Prime Minister went to Japan and laughingly in front of a crowd, he said, "घर में शादी है, लेकिन पैसे नहीं हैं, हा-हा-हा!" That was the level of cruelty and contempt shown for the poor people of India. What happened after demonetisation? Ninety-nine per cent of the cash came back into the economy which is the reason why they have not mentioned demonetisation in this White Paper because they know that it was the biggest glaring failure of the Modi Government. There is also the issue of constantly shifting goalposts. This White Paper is about 2004 to 2014. When Prime Minister Modi got elected, he said, "I am going to give XYZ by 2018." Then the hon. Leader of the House, Shri Piyush Goyal, would correct that and said that this would happen by 2020. Then Prime Minister Modi said, "Two crore jobs per year; Housing for all; and Doubling of farmers' income by 2022." Then that deadline became 2024. But now it has become amazing. Now there are only two things. We will talk about a White Paper from 2004 to 2014 or we will talk about 2047. If you want something, you are not going to talk about the present. If you want something, wait for 23 years till 2047. This is what they did with the Women's Reservation Bill. They did not tell the women of India that until the Census and delimitation happens, it won't be implemented and they have to wait for another nine years. It is not going to happen today. But they are promising to the people during the election campaign. What is amazing is this. I was watching the Mood of the Nation Survey on TV yesterday. It said that over 70 per cent of the people surveyed are worried about unemployment. How many times does the word 'unemployment' figure in this White Paper? Zero. There is no mention of 'unemployment'. This is very funny because Prime Minister Modi had promised two crore jobs per year. He said that in his own statement. It is on the record. What is the reality? In the last five years, 2.7 crore jobs have allegedly been created. Prime Minister Modi has met only 35 per cent of his promised target. Therefore, 'unemployment' is not mentioned in this so-called White Paper. Prime Minister Modi did try to cover up for it. He went to a TV channel and said, "People selling *pakodas* outside the channel office, they are also employees." But this White Paper does not even tell us how many people have

started selling *pakodas* in the last five years. That is the dismal state of unemployment that they can't even tell us how many new *pakoda* sellers they have created.

Sir, price rise is hurting everybody today. What is the reality? Increasing prices of fuel and food items are breaking the back of the poor and the middle class. The people of India have to use up their savings every month just to pay their bills. One statistics or figure as of last year is that the household savings of India are the lowest that they have been in the last fifty years. Then comes my favourite part. Prime Minister Modi said in 2015 that black money will be brought back from foreign countries which will be equivalent to 15 lakh rupees in everybody's bank account. Then later Mr. Amit Shah came and taught us a new word that it is just an election *jumla*. So a new word was added to our dictionary that this was a *jumla*. Prime Minister Modi also claimed categorically that black money brought from foreign countries would be distributed to the salaried class and those who honestly pay taxes. I want to ask through you, Sir, to the citizens of India how many honest taxpaying citizens have got even one rupee of that black money in their accounts in the last ten years. In fact, Rs.10.57 lakh crore have been waived. A big chunk of these loans belonged to fraud businessmen, who were once very happy with Prime Minister Modi. These frauds took up loans, defaulted and left the country. What is more shocking is that Central agencies like the CBI and the ED have not been able to bring either these people back or these funds. But these agencies are busy going after opposition leaders. Ninety-five per cent of the cases against politicians by the ED are against opposition politicians. That leaves 5 per cent. You know who these five per cent are. They are the ones who went into the BJP's washing machine and all the cases against them have stopped. There is not a single BJP leader being investigated for corruption. Sir, I would now conclude. Since this Government has brought out a White Paper on the Indian Economy, through you, I have a few suggestions for the Government. How about a White Paper on women safety? The cover can be decorated with the photo of a famous non-wrestling Lok Sabha Member from their Party. How about a White Paper on the cases of rising hate speech and communal attacks on minorities? This White Paper can also have a cover with a photo of one of their Lok Sabha Members. How about a White Paper on the destruction of Parliament and compromising on its security? Here, you have two options. We can have the White Paper with a picture of 146 respected Members who dared to question the Home Minister or we can have one of their Lok Sabha Member who has a habit of inviting everybody, all and sundry, to the Parliament.

On behalf of my Party, Trinamool Congress, we reject this White Paper, which not only insults the collective intelligence of Parliament but also seeks to*the people of India. I have about a minute left in the allotted time for my maiden speech. I am also aware that since it is my maiden speech, the House gracefully indulges in and allows me to speak. But 'no', Sir; as a proud and self-respecting Member from a proud and self-respecting party of a proud and self-respecting leader, I refuse to further participate in this charade and indulge in the * of this Government. With the promise that the people of India will give BJP the befitting answer to the * in this White Paper and to the Modi Government in the upcoming elections, I and my Party, the Trinamool Congress, will now walk out of the House in protest. Thank you, Sir.

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Amar Patnaik; six minutes. ...*(Interruptions)*... After Dr. Amar Patnaik. ...*(Interruptions)*... I have the list; it has been mentioned here. ...*(Interruptions)*... Tiruchiji, I am following the list. Now, Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, the White Paper on the Indian Economy, which was laid on the Table of the Rajya Sabha yesterday, on the 8th of February, 2024, lays out various macroeconomic fundamentals based on which India will sustain its current economic growth and lead towards a five trillion dollar economy, then a seven trillion dollar economy and would soon become the third largest economy in the world.

Sir, the fundamentals are very strong, as is evident from the fact that the deficit has been consolidating; the trajectory of a glide path is welcome; tax collections are much higher than previous years; gross tax revenues as a percentage of nominal GDP has been improving; direct and indirect tax collections have been increasing, resulting in a decline in fiscal deficit; and the focus on CAPEX leading to crowding in private investment is also taking place. While all these are matters for which we should be proud of, be confident that the economy is in safe hands and doing well, the important thing to realize is that Viksit Bharat will depend on Viksit States. The States will also have to be improved. I am happy to note that in the Budget Speech, the hon. Finance Minister had said that the emphasis would be on the Eastern part of India, the Eastern States. Like the aspirational districts programme or now the aspirational blocks programme, these States are aspirational States. These are the States which

* Expunged as ordered by the Chair.

are going to be the powerhouse or powerful economically for the country if they are nurtured properly. In this connection, I would like to say that taking this particular line of thinking forward, it would be a great idea, which has been a persistent demand of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, to look at Odisha differently from other States considering the scourge of natural disasters that it has faced not just in one or two decades but consistently for the last 70-80 years, resulting in a colossal loss to the fixed infrastructure as well as to the livelihoods of the people. And, therefore, the demand for a special focus State, either by terminology or by changing the sharing pattern from 60:40 or 75:25 to 90:10, could be considered by the Central Government now that the economy is doing well.

Another aspect is increasing the share of Divisible Pool to the States. If we look at the actual transfer that is taking place, it is in the region of 30 per cent to 31 per cent. So, if it can be increased because of the way economy is performing, I think, it would be a great boon particularly to the States like Odisha which needs this money.

There has also been a demand of Odisha, of our hon. Chief Minister, that cess and surcharge which currently is levied, collected, accounted for by the Central Government by law, by provision in the Constitution; I know hon. Finance Minister has several times explained this that this money ultimately goes back to the States through various schemes. However, if it could actually be shared with the States, then the States would have the liberty of knowing exactly where to spend and how much; and they would be in a better position to manage their social sector expenditure. If cess and surcharge were not a part of the gross Divisible Pool, the States would have got Rs.7,32,141.91 crores and Odisha would have got Rs.33,151 crores extra. We are the second-largest producer of coal. Coal is exported from our State but we don't get any portion of the cess that is collected towards revamping the environment that is destroyed because of this extraction. So, we had demanded that if some portion, at least, 60 per cent of the cess in some form could actually be coming to the States, then it would be helpful for us to do environmental protection work around these extractions. We have been also demanding adequate funds for the management of disasters and building disaster resilient power and road infrastructure. Considering the fact that national disasters are a permanent phenomenon in Odisha, our CM has been demanding that if this could be resolved through a one-time grant from the Central Government, then the problem could probably be mitigated to a large extent instead of spending every year.

Sir, we have also been saying that as far as farmers are concerned, there is a need to improve the way the *Fasal Bima Yojana* is performing in the State by giving

some amount of leeway to the State Governments or by improving performance of claim settlement by the organizations. ...(*Time-bell rings.*)...

As far as National Highways are concerned, between 2014-2023, the total length of National Highways in Odisha has only increased by 1,347 kilometres which is just 30 per cent increase while in some other States, the increase has been 80 per cent to 100 per cent. Similar is the position with tele-density and internet density about which he has spoken. ...(*Time-bell rings.*)...

Lastly, what I would like to state about the White Paper is that while we are happy about the fact that the economy is on a right path, on a growth path, on a correct consolidation path, there is a need to look at the States, devolve more funds to the States and spend more money on their social as well as physical infrastructure development. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Dr. Amar Patnaik. *Mananiye Sadasyagan,* Dr. John Brittas has some urgent work and he has to go. Do I have the consent to allow him before Tiruchi Siva*ji*? ...(*Interruptions*)... Please, you have three minutes.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Thank you, Sir. Sir, this is not a White Paper, this is an election paper. Selective amnesia and cherry picking! The Finance Minister has said that 2004 - 2009 was a good period but she gives the credit to the previous Government. Strange enough! Is it not a fact that the Left was supporting the UPA-I which made important decisions and drastic changes like education be made a fundamental right, Right to Information, employment being made a right through MGNREGA and Right to Food Security. The other day, Prime Minister was praising Dr. Manmohan Singh who he ridiculed earlier by calling him "maun-mohan." Now, Sir, the following day, the Finance Ministry is slapping a black paper on Dr. Manmohan Singh. I won't be surprised if tomorrow, this Government would be giving a Bharat Ratna to Dr. Manmohan Singh saying that he was denied Bharat Ratna by Sonia Gandhi. This can happen also. The other day, the Finance Minister spoke about her abundance to Kerala. There were partial truths to confuse the people. On one account, she says that crisis being faced by Kerala, getting its shares reduced from 3.8 per cent to 1.92 per cent was on account of the Finance Commission. On the same breath, she says that she provided so much of revenue deficit grant. Was it not the Finance Commission's grant? The Eighth Finance Commission made the 1971 Census population figures as the basis. But, this Government insisted to make 2011 Census as the basis for the Fifteenth Finance Commission.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I would like to say.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this time should be given to me. This time should be given to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: On the condition that he has been invited to speak out of turn because you are going away, you won't be here to listen to my reply, I would like to say, now, Sir, that many of the things that he is saying are sprucing up his speech but words which I have not used. So, I will still take the liberty to say in my reply when hon. Member will not be here but I am sorry, he is taking liberties with my words.

DR. JOHN BRITTAS: Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will have it. Please.

DR. JOHN BRITTAS: You should give me forty seconds which she has taken.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

DR. JOHN BRITTAS: See, she can make a reply and I will go through the records and see that.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: You may not be here.

DR. JOHN BRITTAS: Madam, I will see the video. ...*(Interruptions)*... She harps on co-operative federalism. In 2010-11, it was 8.5 per cent which was mopped up through surcharges and duties. Now, it has reached 28 per cent and this tantamounts to the fact that Kerala has lost, at least, Rs. 20,000 crores at the effective devolution to the States instead of 41 per cent recommended by the Finance Commission, it is merely 30 per cent. She can challenge me, if I am wrong on that. Our own revenue expenditure is 78.7 per cent whereas it is 54 per cent in U.P. and in Madhya Pradesh (M.P.), it is 51 per cent. You want to spend ten per cent, fifteen per cent and twenty per cent on Centrally-sponsored schemes. You want to have branding even for selfie

corners, even for putting up Modi*ji*'s photographs. Sir, what is happening in this country? I mean, can you turn the State schemes to be a propaganda mission for the BJP Government here? And, even for ration shop slips, you want lotus there. Parallelly, instead of supporting the PDS, they are distributing *Bharat Aata, Bharat dal,* everything, by-passing the State, even then, they claim that they are on the path of co-operative federalism. I salute those great souls who have been bestowed with Bharat Ratna. ...(*Time-bell rings*.)... Sir, one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Conclude now.

DR. JOHN BRITTAS: I salute them. When they are pelting, I would say, bullets on the *Kisans*, they will talk in terms of Bharat Ratna to a *kisan putra*. Sir, protesting against the discrimination shown to Kerala, we are walking out and we are also not party to any move to communalize the political situation. Thank you, Sir.

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber*.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Mananiya* Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, this Government, at the end of this term, is extending the House for a day and at the expense of the tax payers' money and is making use of this forum for election propaganda. This is a very important debate and we all wished it to be because the White Paper has brought out the ten years, they say as their achievements and setbacks of the UPA Government. But, actually, it is not so. If we have to explain, we need adequate time, whereas everything is the prerogative of the Government. You extend the House for a day--yes you are boss--and you fix the time and you take more time but you do not even give the time. I would like to say that after the 2024 elections, when the 'I.N.D.I.A.' alliance wins and takes over the power, we will bring out a White Paper on this Government and we will give them adequate time, not strangling their voice. Sir, the Opposition's voice should not be strangled. The TV does not focus on us, we are not given the mike, we are not given time, but we have to let out our voice. What for we have come here? We are representing the people from various regions of this country. So, we have to express something means we need time, at least, to speak out. So, the ruling party and opposition parties have to be treated equally, whereas it is not so; that is different. First of all, whether this Government has got the credibility to bring a White Paper pointing fingers at the earlier Government, the UPA! Everyone

knows and the Finance Minister knows very well that when you point a finger at another, don't forget three fingers pointing towards you. You say that the UPA Government has failed in many aspects. Sir, I would like to say only one thing. Our founder leader, Anna, who made an indelible mark in the Second Chamber of the Parliament, that is, in this august House and later became the Chief Minister of Tamil Nadu, during his tenure, there was a student agitation. The student agitation mounted much and the police came and said that they are not able to control them and they need shooting order. The Chief Minister refused. They said, "Sir, they are going to the railway station to set fire on the railway compartments which will cause great damage." But Anna, the Chief Minister said, "Don't do that. If they burn a rail compartment, I can build another rail compartment. But if you shoot a student, I cannot bring back his life to his parents." That is the real gesture and responsibility of a leader. Sir, this Government has brought a White Paper, let them say. The hasty farm laws which were enacted in this Parliament, when the House was not in order, were later revoked because of not having applied their mind; they took away 700 lives of the farmers only during that agitation. Because of those farm Bills, many were agitated and 700 farmers died, and the responsibility, rather, the credit goes to this Government. Hundreds of people died before the banks when they stood in the lines to change their currency notes when the demonetisation came, and the credit goes to this Government. Hundreds of migrant workers were strangled because of just four-hour notice when the first lockdown was announced. They were stranded along and hundreds of migrant workers died, and the credit goes to this Government.

Sir, I want to stick to only two points. Number one is agriculture because I have started with agriculture. What happens is that the insurance companies under the *PM Fasal Bima Yojana* have made a profit of Rs.40,000 crores, while according to the National Crime Records Bureau, in 2022, India saw 11,290 suicides in the farming sector. Out of these victims in 2022, about 5,207 were farmers and 6,083 were agricultural labours. Take for example, the GST. The Budget support for agriculture is coming down for the past two years. The GST on agriculture items and equipment is 12 per cent; on tyres, other parts, tractors, machines for processing and milling cereals is about 18 per cent; on fertilizers, it is 5 per cent; on pesticides, it is 15 per cent. The fertilizer subsidy has been reduced by 13 per cent. The spending on agriculture is only 2.67 per cent. So, this Government is not taking care of the agriculture. India is basically an agricultural country. I think it is the right time, I should say, that the GFC (Global Financial Crisis), which the White Paper has itself told about, when the whole European countries, when America was just 0.8 per cent in GDP; the U.K., at 1.7 per cent; Germany was one per cent; Japan, 1.5 per cent;

France, 1.4 per cent; Canada, 1.9 per cent; India was at 8 per cent during the UPA-I. During the UPA-I, the GDP was 8 per cent. When the economic recession took away the whole of the Western countries, India withstood only because of the agriculture sector, because of the public sector undertakings, because of the MSMEs. All these sectors are being suppressed nowadays.

1.00 **P.M.**

Sir, PSUs are being disinvested, which are all profit making. MSME which contribute 29 per cent to the GDP provides 10 crore employment and 45 per cent export is being not taken care of. Sir, I will just take one minute. I would like to add one more thing. On unemployment, everyone told that this Government, which is in power now, during the elections, assured everyone that every year, two crore employment will be generated and given, but it was not given whereas unemployment in 2012 was one crore, and now it is four crores. It has increased whereas instead of giving employment, unemployment has soared up. During the UPA, 75 lakh non-farm jobs every year were created. ...(*Time-bell rings.*)... In this Government, only 29 lakh non-farm jobs every year. Sir, one in every three persons is running for a job unsuccessfully. Two unemployed persons commit suicide every year. And, very importantly, Sir, 9,75,000 posts are vacant in the Central Government offices and 30 lakh positions was estimated... ...(*Time-bell rings.*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I will take one more minute. That is why I said it is very important, again.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken one minute.

SHRI TIRUCHI SIVA: Time again strangles our throat, Sir. What I am trying...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva, let me intervene. You are a very senior Member. You know that this discussion is for two-and-a-half hours.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, why should we take it in a Short Duration Discussion?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Short Duration Discussion is for two-and-a-hour hours. Please finish. You know the timing rules.

SHRI TIRUCHI SIVA: Give us more time and discuss. If at all they are very clear about themselves, they should give time to us and listen.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: Up to 30 lakhs positions are estimated to exist in Government positions across India, not filled up. These are the situations in the country. Sir, in the Indian Railways, staff strength have fallen from 17 lakh to 11 lakh employees in 2023. The number of vacancies in PSU's workers have fallen from 17.3 lakhs to 14.6 lakhs. Contract workers without job security has almost doubled from 17 per cent to 36 per cent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, this is the situation. Unemployment is soaring up. In agriculture sector, the farmers are committing suicide.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I will conclude. The Tamil Nadu Government which has been affected by very severe flood in December, 2023 have sought for relief fund. The Chief Minister met the Prime Minister. Despite that the delegation of Members of Parliament met the Home Minister, despite that Shri Raj Nath Singh, Defence Minister visited us, despite that, we are pleading. Nothing has been given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Dr. Ashok Kumar Mittal.

**डा. अशोक कुमार मित्तल** (पंजाब): उपसभापति महोदय, आज आपने मुझे भारत की अर्थव्यवस्था पर, व्हाइट पेपर पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। इस पर हम आज इस सदन में चर्चा कर रहे हैं और कल इस पर लोक सभा में चर्चा हुई थी। मैं सबसे पहले देश को बधाई दूंगा कि माननीय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और डा. एम.एस. स्वामीनाथन जी को 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया है। श्री नरसिम्हा राव जी economic reforms के लिए जाने जाते हैं, डा. स्वामीनाथन जी agriculture reforms के लिए याद किए जाते

हैं और हमारे चौधरी चरण सिंह जी किसानों को आगे ले जाने के लिए याद किए जाते हैं। मैं इसके लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

सर, इस 60 पेज के व्हाइट पेपर में मुख्यतः दो चीज़ों पर स्ट्रेस दिया गया है, एक यूपीए के कार्यकाल में economic mismanagement हुआ है और दूसरा सरकार अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ले आई है, इन दो चीजों पर स्ट्रेस है। हम सब इस बात पर सहमत होंगे कि सरकार चाहे नेहरू जी की रही हो, शास्त्री जी की रही हो, अटल जी की रही हो, डा. मनमोहन सिंह जी की रही हो, उन्होंने कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा, अन्यथा आज हम इस स्थिति पर न होते। एक बात अर्ज़ करूंगा,

*'तारीफ खुद की करना फिज़ूल है,*
*खुशबू खुद बता देती है कि कौन-सा फूल है।'*

सर, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी देश में अच्छे काम हुए हैं, उनको व्हाइट पेपर में डालना चाहिए और जनता के सम्मुख लाना चाहिए, चाहे वे किसी भी सरकार के समय में हुए हैं। सर, यह देश का रिपोर्ट कार्ड है और रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जैक्ट के अलग-अलग मार्क्स होते हैं। किसी के किसी सब्जैक्ट में कम मार्क्स आ सकते हैं, किसी में ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस व्हाइट पेपर को व्हाइट ही रहने दें, इसे ग्रे न करें।

सर, मैं कल जम्मू-कश्मीर के बिल पर बोल रहा था। भारत सरकार ने या वहाँ की सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जो अच्छे कार्य किए हैं, मैंने उनकी तारीफ की। माननीया मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और अपने जवाब में कहा कि हमें अपोजिशन में ऐसे लीडर्स चाहिए, जो सही को सही और गलत को गलत बोलें, सरकार ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करें। इसके लिए उन्होंने खुशी की भावना दिखाई। सर, मैं भी आपसे यही चाह रहा हूं कि जिस सरकार ने भी अच्छे कार्य किए हैं, उनको बताएं। हमारी सरकार कभी भी नहीं थी, लेकिन जिस सरकार ने जो भी अच्छा कार्य किया, उसको भी बताएं और जो बुरा कार्य किया है, उसको भी बताएं।

सर, यदि आपने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, तो यूपीए सरकार मनरेगा लेकर आई; आपने जन-धन योजना शुरू की, तो यूपीए सरकार यूएस-इंडिया न्युक्लियर डील लाई; आपने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की तो यूपीए सरकार ने अपने पहले काल में देश को अभी तक की सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ दी; आपने स्किल इंडिया शुरू किया, तो यूपीए सरकार ने नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की नींव रखी; आपने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, तो यूपीए सरकार ने नेशनल फूड सिक्युरिटी बिल में गरीबों के लिए मुफ्त राशन शुरू किया; आपने आत्मनिर्भर भारत का विज़न दिया, तो यूपीए सरकार ने नेशनल अरबन लाइव्लीहुड मिशन दिया। सर, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, जब हमने इकट्ठे काम किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए टीम इंडिया के तौर पर आगे बढ़े।

महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ मुद्दे रखना चाहूंगा। पहला मुद्दा बेरोजगारी का है, जो कि युवाओं से जुड़ा है। सर, इस पेपर में कहीं पर भी बेरोजगारी पर बात नहीं की गई है। हमारी बेरोजगारी सात प्रतिशत है। हम सबसे युवा देश हैं, लेकिन दस लाख सरकारी पद रिक्त हैं। सरकार ने खुद ही कहा है कि जब उन्होंने आवेदन मांगे, तो सात लाख नौकरियों के लिए बाइस करोड़ आवेदन आए। हमारी यह हालत है! प्राइवेट सैक्टर में भी काफी mass layoffs हो रहे हैं। January में भी तीस हज़ार लोगों को निकाला गया है।

सर, मैं दूसरा बिंदु डिफेंस के बारे में बोलना चाहता हूं। चीन हमें आँखें दिखाता रहता है, पाकिस्तान में भी शायद फिर से Army-sponsored सरकार आ जाए। हमें Defence के लिए जितना budget चाहिए, हमारी Defence के लिए जितनी requirement है, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं? मैं माननीया मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा-सा गौर करें।

महोदय, तीसरा मुद्दा, जो देश की ग्रोथ से संबंधित है, वह Artificial Intelligence का है। Artificial Intelligence आ रहा है और अलग-अलग सैक्टर्स ने अनुमान किया है कि यह भारत के जीडीपी में अकेले 1 Trillion Dollar का योगदान कर सकता है। क्या हम उस advantage को लेने के लिए तैयार हैं, as a first mover? मैं माननीया मंत्री जी से कहूंगा कि कृपया उस तरफ भी देखें।

महोदय, जो deepfake के केसेज़ बढ़ते जा रहे हैं, हम उसको regulate करने के लिए क्या कर रहे हैं?

महोदय, चौथा मुद्दा, जिस पर मैं बात करना चाहूंगा, वह mining का है। हमारे देश में minerals की काफी availability है, लेकिन हमारा जो mining sector है, उसमें अभी भी जो legacy issue है, वह उससे प्रभावित है। हमारे पास adequate mineral exploration नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दें और जरूरत पड़े, तो एक mining regulator लगाने की तरफ भी देखें।

महोदय, मेरा सुझाव है कि जहाँ भी ठीक लगता है, व्हाइट पेपर पर उसको देखें और revise करें, kindly ego issue न लाएं। उसको देखते हुए आपको जहाँ ठीक लगता है, वह कीजिए, ताकि हमारे सामने जो भी चुनौतियाँ हैं, हम उनका मुकाबला करें और सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित न रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीया मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगी।..(**समय की घंटी**).. मैं आखिर में छोटी-सी दो पंक्तियां कहकर अपनी बात खत्म करूंगा,

*'वो दोस्त मेरी नज़र में बहुत मायने रखते हैं,*
*जो वक्त आने पर मेरे सामने आईने रखते हैं।'*

आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपसभापतिः** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ए. डी. सिंह जी, आप बोलिए, आपके पास चार मिनट हैं।

**श्री ए. डी. सिंह** (बिहार)**:** महोदय, यह सरकार पूरे नहीं किए वादों की सरकार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि,

*'तिरे वादे पर सितमगर अभी और सब्र करते*
*अगर अपनी जिंदगी का हमें एतिबार होता।*
*कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है*
*यह वक्त है जनाब, बदलता जरूर है।'*

The Government is very clear on the While Paper. It says that you may not be doing, but everybody else is doing well. Basically the White Paper is just a celebration

of the Government record, but the notable promises made during the past few years like the *Ujjwala Yojana*, double income of the farmers, have been left on the wayside and now it has been replaced by another narrative, *Viksit Bharat*.

First of all, I want to know about the unity and sovereignty of the country with respect to the White Paper. One retired Member of the ruling party of this House has been saying that 4,000 kilometres of our land is in Chinese hands. I get perplexed and confused when the Government says that nothing is in their hands. Then why can't the Government come with a white paper of these 18-20 rounds of discussion that our Generals are having with the Chinese side? Why is the Government suppressing it? For example, in 2017-18, the consumption survey was scuttled midway because the rural consumption was falling very badly. I would request the hon. Finance Minister, that from 2004 till now, can we get a data regarding the Finance Commission, that in each of the years how many regular taxes were converted into cess? Though the Finance Minister did answer my question in her reply to the Budget Speech, this percentage was not elaborated. Private investment is hardly there and hence we are not getting foreign investment because the foreign investor first sees how much are the Indian companies investing and the Government is also going in the South Korean model, that let us make some corporates very big. That is wonderful, I would say, but the difference between the South Korean corporates and the Indian corporates is that they innovate new products and make mass production and make the company big financially. Here, the big corporates only feel that by adding assets, they are becoming big. As in the rural market, there is no mass scale demand because the purchasing power is almost nil. So, there should be efforts in the capital investment; the Government says that it has increased five times in the last few years, but it is mainly in the infrastructure sector. I would be happy if the capital expenditure is more in education, sanitation, health, where actual jobs can be created. "The Government has made many airports. That is wonderful. Ayodhya is an exception because Ayodhya airport will, definitely, bring a lot of jobs and other things because Ayodhya has become a religious tourism place. The other airports, of course, are needed, but that will not add to any employment. If we see the number of unpaid workers, it has reached to almost 95 million. (*Time-bell rings.*) One minute, Sir. As per the International Labour Organisation, work means whoever is getting paid. Just because the whole family is working in the land, so, basically, they are all unpaid workers. So, we have not created jobs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. We have more speakers.

SHRI A. D. SINGH: One minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not one minute. Please conclude.

SHRI A. D. SINGH: Coming to agriculture and rural development, the Government has revised the Budget for this particular year, but I fail to understand that the Revised Budget, which is very huge, how they will spend in the next two months.Thank you.

**श्री राम नाथ ठाकुर** (बिहार): उपसभापति महोदय, आपने मुझे श्वेत पत्र पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

किसी विद्वान ने ठीक ही कहा कि लोकतंत्र में श्वेत पत्र जारी करना अच्छी बात है। उद्योगों के घराने भी श्वेत पत्र जारी करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि नीचे से नीचे तक लोगों को यह पता चले कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे जो श्वेत पत्र लाए हैं, यह बहुत अच्छा काम किया है। पिछले वर्षों में कांग्रेस के जमाने में 26 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उसको यहाँ लाकर उन्होंने बहुत पारदर्शिता का काम किया है।

महोदय, मैं आपसे दो बातों के ऊपर निवेदन करना चाहता हूँ। समय कम है, लेकिन मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। मैं कहीं आज पढ़ रहा था, बहुत अच्छे विद्वानों ने जो लिखा है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 1963 में कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, डी. संजीवैय्या को यह कहना पड़ा था कि 1947 में जो **कांग्रेसी भिखारी** थे, वे आज करोड़पति बन बैठे हैं, झोंपड़ियों का स्थान शाही महलों ने और कैदखानों का स्थान कारखानों ने ले लिया है। यह कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, डी. संजीवैय्या ने कहा है। कारण क्या है? यह कांग्रेस के नेता ने कहा है। 1948 के जमाने में पहला घोटाला हुआ था - जीप घोटाला। जब घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में ऐसा कहा। इसका तो संज्ञान लेना चाहिए। भारत सरकार ने यह जो काम किया है, यह काबिले तारीफ है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और 26 लाख करोड़ के बारे में आपने जो लोकतंत्र में यह दर्शाने का काम किया है, यह भी अच्छा काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था। अभी बहुत चर्चा चल रही थी, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, नरसिम्हा राव जी के बारे में, ...(**समय की घंटी**)...

**श्री उपसभापति:** आप कन्क्लूड करिए।

**श्री राम नाथ ठाकुर:** तो चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया था और बिना कहे हुए समर्थन वापस ले लिया। उसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अच्छी बातों को लागू करने का काम किया था, उस कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को कांग्रेस की सरकार ने गिराने का काम किया था। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी ने जो इन लोगों को

भारत रत्न देने का काम किया है, ...(**समय की घंटी**)... यह बहुत ही अच्छा काम किया है। जनता के लिए यह खुशी की बात है, किसानों के लिए यह खुशी की बात है। धन्यवाद।

**श्री जयराम रमेश** (कर्नाटक): सर, कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को भारतीय जनसंघ ने गिराया था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं गिराया था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. M. Thambidurai. You have three minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, on behalf of AIADMK and my party leader, Shri Edappadi Palaniswami, I rise to participate in the discussion on the White Paper on the Indian Economy presented by the hon. Finance Minister to this House on 8th February, 2024.

Sir, in Para 2, hon. Minister specifically mentioned that 15 major scams took place during that period. I would like to state here that during the entire period of the UPA, from 2004 to 2014, the DMK was part of the Government. And, whatever corruption took place during that period, DMK was also a party to everything. Sir, Part-2 of the White Paper exclusively deals with corruption made by the then Government. So, let me narrate how DMK was party to those corruptions. There is a mention about the 2G scam in which the then Union DMK Minister went to jail. There was a loss of about Rs. 1.76 lakh crores to the Government. Along with the former DMK Minister, the daughter of former Chief Minister of Tamil Nadu and sister of the present Chief Minister also went to jail. Presently, the case is in the appellate court. They are saying that they went to the court and the stay is there. No; the stay is not there. An appeal has been made. The signing Judge clearly said that there was a serious crime but because the CBI did not cooperate, he made that kind of observation. But the CBI has gone in appeal. Therefore, the present case is there.

The Minister also mentioned about the Aircel-Maxis case in which former Finance Minister was sent to jail and his MP-son is also facing serious charges. This case is also under trial now. The former Union Minister, now a Lok Sabha Member, grand nephew of the former DMK Chief Minister, abused his official position as the then Minister of Communications and Information Technology in the UPA-1 Government and got private telephone exchanges installed at his residences, which were used for business transactions of the Sun Network, owned by his brother Kalanithi Maran. The present DMK Government in Tamil Nadu is also full of corruption. The former DMK Higher Education Minister, one of the DMK Ministers in the present Cabinet, and his wife were convicted recently under the PMLA. The case is pending. One DMK Minister, without portfolio, who is also in prison, is facing

charges under the PMLA. The Tamil Nadu Chief Minister will not ask for his resignation. This is a wonderful thing going on in Tamil Nadu! Sir, there is another interesting thing. The former Finance Minister, Madam knows very well, and also a Minister presently, has said that the present Chief Minister and his family together made more than Rs. 30,000 crores, just in a year! (*Time-bell rings.*) This has to be seriously taken up. I am just concluding, Sir. When Edappadi Palaniswami raised the issue, the former Minister and also a Lok Sabha Member presently, made derogatory remarks about Edappadi Palaniswami's mother. This is a very serious thing. The hon. Finance Minister knows very well how the DMK Government is indulged in a lot of corrupt practices. Let them talk or not, but whatever is mentioned in the White Paper, it is correctly mentioned as to what the UPA Government did. Thank you very much, Sir.

**श्री प्रकाश जावडेकर** (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, नमस्ते। हर सरकार की एक पहचान होती है। यूपीए सरकार की पहचान भ्रष्टाचार है और यही रही है, इसीलिए लोगों ने उसको सत्ता से बाहर किया। कोयला भ्रष्टाचार मामले में, मैं ही व्हिसल ब्लोअर था। लोक सभा के सांसद, हमारे कलीग हंसराज अहीर उस कमेटी में भी थे। उनको बहुत जानकारी थी। हम दोनों ने उसका अध्ययन करके उसका इतना फॉलो अप किया कि वह घोटाले के रूप में सामने आने लगा। उसमें क्या घोटाला था? उस घोटाले के दो पहलू थे। 125 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज़ को या पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज़ को 50 लाख करोड़ के कोल भंडार फ्री में दे दिये, फ्री में। सर, कांग्रेस के जमाने में जहाँ राशन कार्ड फ्री नहीं मिलता था, वहाँ 50 लाख करोड़ के कोल भंडार फ्री में दे दिये गये। First come, first served. इसमें वास्तविकता क्या है? मुझे उस समय अन्दर की भी जानकारी मिली कि एक चिट्ठी आती थी। 'चिट्ठी आयी है, आयी है..' कभी-कभी एलोकेशन कमेटी की मीटिंग्स लम्बी चलीं, क्योंकि नहीं आयी थी। जब चिट्ठी आयी, तब एलोकेशन हुआ। लेकिन ये एक चीज़ भूल गये, जिससे यह साबित हुआ कि इसमें घोटाला कैसे है। समझिए कि 'ए', 'बी' और 'सी' - तीन लोगों ने कोल का ब्लॉक माँगा है। इसमें 'बी' को दिया गया है, तो 'ए' और 'सी' को क्यों नहीं दिया गया, इसका कारण नहीं लिखा और 'बी' को क्यों दिया गया, इसका कारण नहीं लिखा। इसीलिए सारे कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन फाइनली कैंसल हुआ। लेकिन उसके पहले भी एक कहानी है। हम दोनों, मैं और हंसराज अहीर सीवीसी के पास गए। सौभाग्य से वे भी पहले कोल सेक्रेटरी रहे थे। उन्होंने कहा कि घोटाला तो है, लेकिन सबूत दीजिए। अब सबूत हम कहाँ ढूँढ़ते? हम तो विपक्ष में थे। लेकिन एक न्यूज़पेपर में advertisement आया कि मुझे अभी जो कोल ब्लॉक मिला है, उसे बेचना है, जिसको भी यह कोल ब्लॉक चाहिए, वह मुझसे संपर्क करे। हम यही सबूत लेकर गए और सीवीसी ने सीबीआई इन्क्वायरी का आदेश दिया। उस सीबीआई की जाँच नहीं चली, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट टाइमली देनी पड़ती है, उसके लिए लॉ मिनिस्टर के केबिन में वह सीबीआई की रिपोर्ट लिखी गई। यह भी साबित हुआ, उनको जाना पड़ा। उसके बाद court monitoring शुरू हुई और finally सारे coal blocks खत्म हुए। यह चिट्ठी क्यों आती थी? आप natural resources फ्री दे रहे थे और मोदी सरकार आते ही उसका auction शुरू हुआ।

जितने भी coal blocks बाँटे गए, उन सबका पैसा तिजोरी में जमा हुआ। यह फर्क है भ्रष्टाचारी सरकार में और हमारी सरकार में।

सर, मुझे पर्यावरण मंत्रालय में काम करने का मौका मिला। मेरे आने से पहले वह टैक्स मिनिस्ट्री के रूप में जाना जाता था। मैं एक उदाहरण दूँगा, जिसको सुन कर आपको आश्चर्य होगा। Karwar में नेवी का प्रोजेक्ट 'Seabird' बंदरगाह, जिसका मैंने परसों भी उल्लेख किया था, यह बनना था, लेकिन तीन साल तक परमिशन नहीं दी गई। नेवी के सारे प्रमुख अधिकारी मंत्री से मिलने के लिए गए, तो मंत्री जी ने कहा कि आप सारे अधिकारी क्यों आए हैं, कोई तो contractor होगा, जो इसको बनाएगा, आप उसको भेजिए। सर, यह फैक्ट है। उस समय जो अधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने मुझे यह बताया है। एक जमाना था, जब पर्यावरण मंत्रालय में no-go; एक जमाना था - tax; without tax nothing. आपको यह जान कर और ताज्जुब होगा कि उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और उनके PMO ने बहुत महत्व के 15 infrastructure प्रोजेक्ट्स पर्यावरण परमिशन के लिए भेजे, लेकिन उनको भी दो साल तक परमिशन नहीं मिली और मैंने दो महीने में परमिशन दी। मैंने मनमोहन सिंह जी को कहा कि यह देश के हित में है। मोदी जी ने हमें सिखाया है कि देश प्रथम है और देश के लिए काम करना है।

सर, जब मैंने कार्यभार संभाला, तब 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे। हमने साढ़े चार महीने में वे सारे प्रोजेक्ट्स clear किए। अगर देश के विकास को गति नहीं मिलेगी, तो तरक्की कैसे होगी? विकास को गति मिलनी चाहिए। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा।

सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का हम मंत्रियों के कारोबार में कभी हस्तक्षेप नहीं था। एक मंत्र था कि देश के हित में जो है, वह करना है। Environment Ministry में application करने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते थे, इसलिए हमने online application की शुरुआत की। ये सब देश को अच्छा सुशासन देने और आर्थिक तरक्की करने की दिशा में कदम हैं। ये सारे आर्थिक महत्व के प्रोजेक्ट्स pending थे, जिनको हमने clear किया। तब ये सब लोग instant permission और clearance, clearance चिलाते थे। इन लोगों ने मेरे खिलाफ और हमारी सरकार के खिलाफ इस तरह के campaign चलाए, लेकिन यह चला नहीं, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। जिसका ठीक नहीं था, उसको clearance नहीं दी, जिसका अच्छा था, उसको clearance दी, उसको रोका नहीं - यह हमने काम किया है। इसलिए मुझे बहुत अभिमान है।

निर्मला जी, मैं आपको भी एक सुझाव दे रहा हूँ। ये लोग पूछते हैं न कि दो-दो करोड़ जॉब्स कहाँ मिले? मैं भी बैंक में काम करता था और employment-promotion विभाग का काम देखता था, इसलिए बेरोजगारों के बीच जाता था, बेरोजगारों की रैलियाँ करता था। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और एच. एम. पटेल वित्त मंत्री थे। उस समय हर ब्रांच में हर महीने दो यूथ को कर्ज देने का कार्यक्रम था, उसको मैं देखता था।

उसमें जो मेरा अनुभव है, उसके कारण मुझे पता है कि अगर पाँच लाख का कर्जा दिया जाता है, तो उससे दो-चार नये रोज़गार तैयार होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें ऐसा है कि चूंकि individual credibility है, इसलिए बैंक यह जानकारी नहीं दे सकते। मैं निर्मला जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने बीच में एक बार उनको लिखा भी था कि हर बैंक से यह बताने के लिए कहिए कि आपने जो मुद्रा लोन्स दिए, उनसे कितने नए रोज़गार तैयार हुए? यहाँ मैंने खुद 500 से ज्यादा

मुद्रा लोन्स लेने वालों के testimonials लिए हैं, जिनमें से किसी ने दो, किसी ने चार और किसी ने छः लोगों को रोज़गार दिया है। सर, जो 45 करोड़ मुद्रा लोन्स दिए गए हैं, उन 45 करोड़ के मुद्रा लोन्स से कम से कम 25 करोड़ नए रोज़गार तैयार हुए हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। उसका एक बार सर्वे करके नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वे करके यह हो सकता है, यह मेरा पूरा विश्वास है।

सर, अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने एयर इंडिया में क्या भ्रष्टाचार किया। Unusual acquisitions, bilateral agreements, एक पूरी कंपनी डुबा दी और भ्रष्टाचार के एक-एक ऐसे मसले तैयार होते रहे, जिसके कारण इस सरकार की पहचान भ्रष्टाचार थी, तरक्की रोकने वाली थी और उसे मोदी सरकार ने करैक्ट किया, इसलिए मैं इस व्हाइट पेपर का स्वागत करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डा. के. केशव राव** (तेलंगाना): सर, यूँ तो मुझे बहुत सारी बातें कहनी थीं, क्योंकि यह 60-पेजेज़ का व्हाइट पेपर है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका रीज़न क्या था, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोई intention होती है। If the intention is very good, then, it is all right because economy is recovering. Everybody is accepting that. Critically, we might sit here and talk anything. But we know that it is on its way to recovery. It is not that everything is good but it is recovering.

यह जो व्हाइट पेपर आया है, इसका मतलब क्लियर है। हमें एक तो इसकी timing के बारे में सोचना चाहिए, दूसरा इसके context के बारे में भी सोचना चाहिए। इसकी टाइमिंग यह है कि आप इसको इलेक्शन के ठीक पहले ला रहे हैं। आपने टेम्पल के बारे में भी एक प्रस्ताव दिया है, जिसे आप शायद इलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। यह व्हाइट पेपर, which is about Indian economy, इससे आपने इकोनॉमी से ज्यादा अपने opponents या पहले की गवर्नमेंट को टारगेट किया है, जैसा कि अभी जावडेकर साहब बोल रहे थे कि 'Every Government is identified by some kind of a thing and earlier Government by its corruption'.

All that you have said here, Madam, is one thing that we all know through your Economic Surveys or your Budget Speeches or the speeches of the Prime Minister; and all these things are well known, your ten-year decadal achievements. Whether we agree with it or not is another matter. These are known to us. But what is the big thing that you have tried to tell us? That is what we are trying to know. Now, you are trying to talk about the earlier Governments. If I give the figures, -- earlier, the Congress Leader has spoken on that -- if I give that, it will put you to shame. That we understand. What you said is, "We took up at a time when the entire nation was at an absolutely downcast level." But you took up at a time when the GDP was much, much more that what you have today. That means, you had 6.7 per cent GDP level and today you are somewhere at 5.3 or 5.2. That itself tells that you have started with some kind of a bad intention. In criminal jurisprudence, when we have a bad intention, that becomes a crime. When you have a clear intention of telling us,

informing us all, as to what exactly is the position, it is very right which I would readily welcome. I start with your claim of '25 crore people being pulled out of the poverty line.' While the World Bank's figures that I was looking into, it was 27 crores during the UPA Government. Now, the reason is the change in parameters. I have seen the parameters; the ten parameters that they have used and the twelve parameters that you have used is for the change. But, nonetheless, even if I look into it -- I have not calculated it as I am not an expert in this; I am not an Economist —it is, certainly, more than 25 crores as far as the UPA Government is concerned. Now, I am not trying to quote figures here. Madam Finance Minister, when you brought a White Paper on the Indian Economy, I thought you would talk about the fundamentals of economy, how we are growing, the fiscal deficit, etc. You have brought down the fiscal deficit. If you can really maintain that, there is nothing like that. You have concentrated on CAPEX. If you can really improve, nothing like that. Other than these two, what really matters in any nation's economy is its people. People are interested in employment. I do not wish to repeat what Mr. Siva or Mr. Gokhale have said. They spoke at length about unemployment but you did not mention about it. Now, coming to prices, people talked about it. I have got with me figures about prices, but there is no use of my giving you figures because they really make us sad. I don't wish to use all the statistics but quote a few examples about prices. The price of cylinder was Rs. 903, it has risen to ...*(Interruptions)*... Petrol used to cost Rs. 71 earlier, now it has become Rs. 97; diesel used to cost Rs. 55, it has become Rs. 90. Similar is the case with mustard oil and other commodities. Thus, prices have gone up. सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इकोनॉमी का बात करते हैं, उसे evaluate करने के लिए करेंसी उसका बेस होती है। करेंसी से fiscal health चेक होती है। आपने करेंसी की सबसे बड़ी revolutionary thing Demonetization किया है। उस demonetization के बारे में यहां कुछ नहीं बताया गया। That is the basis on which we could have evaluated what exactly the economic situation is ...(**समय की घंटी**)... सर, मेरा बोलने का कितना टाइम रह गया है?

**श्री उपसभापतिः** आपका बोलने का समय ऑलरेडी खत्म हो गया है। You have already exhausted your time.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I would take only one minute more and close it.Madam, I do not wish to repeat everything, but there is one paper which the Congress friends presented as a rebuttal. I want you to go through that. I would use one last sentence since there is no time left. Madam, there is one point that you made yesterday, about devolution of funds. We know that you can't do anything there because this is something that the Finance Commission does. We, in the Parliament, talk to you not

because of what the Finance Commission does; we tell you so that you change your principles once you come to know of it. We are a multi-national nation. Let us understand this. We are a multi-national nation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. This is your personal view.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, we are evolving a method to integrate ourselves in one nation. We are one nation with so many States who have joined together. So, there is always unity. There has to be unity in diversity. We must find unity in the diversity. Let me talk about the South when it comes to devolution of funds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

**डा. के. केशव राव:** साउथ में तेलंगाना को आपने 2.10 परसेंट दिया है, आंध्र प्रदेश को 4.05 परसेंट दिया है, कर्णाटक को 3.7 परसेंट दिया है, तमिलनाडु को 4 परसेंट दिया है और केरल को 1.9 परसेंट दिया है। आपने southern states को टोटल 15 परसेंट दिया है। The share of other States is 84 per cent. हम जब यह देखते हैं - यह हो सकता है कि कमीशन ने कुछ decide किया हो, आप प्लीज़ अपना mind लगाइए और यह सोचिए कि किस तरह से ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... Please, Keshava Raoji, you have already crossed the time-limit. Shrimati Priyanka Chaturvedi. ...(**व्यवधान**)... You have three minutes.

**श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी** (महाराष्ट्र): सर, मैं मानती हूं कि इस Short Duration Discussion को 'White Paper on Indian Economy के बजाय अगर 'Election Paper due to the upcoming Indian Elections' रखा जाता, तो ज़्यादा सही एजेंडा होता। मैं बताती हूं कि क्यों, क्योंकि यहां पर इलैक्शन नहीं, economic mismanagement *versus* economic excellence दिखाने की बात की गई है। मैं इस पर कोई बुराई नहीं करना चाहूंगी, बल्कि कुछ आंकड़े देकर जनता के विवेक पर छोड़ना चाहूंगी। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच में जो nominal GDP growth थी, वह 14.95 परसेंट थी, जो वर्ष 2014 से 2024 के नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में 10.31 परसेंट है। यूपीए era में मनमोहन सिंह जी के समय GDP growth rate 6.8 परसेंट था, जो इनके समय में 5.9 परसेंट है। यूपीए के कार्यकाल में fiscal deficit 4.7 परसेंट था, जो NDA के कार्यकाल में 5.1 परसेंट है। मैंने mismanagement और excellence में difference बताने की कोशिश की है। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी चार स्तम्भों पर देश के प्रधान मंत्री बन कर आए थे, महंगाई की मार, नारी पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और युवा बेरोज़गार। अगर मैं महंगाई की बात करूं, तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है और हमने इन्फलेशन से बचाने का काम किया है। अगर आप पूरी दुनिया की पर-कैपिटा इन्कम देखेंगे और हमारे देश की पर-

कैपिटा इन्कम और एक्सपेंसेज़ देखेंगे, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। एलपीजी में 120 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल में 37 प्रतिशत, डीजल पर 64 प्रतिशत, मस्टर्ड ऑयल पर 59 परसेंट, आटे पर 59 परसेंट और दूध पर 71 परसेंट महंगाई बढ़ी है। अब मैं महिला पर वार की बात करना चाहती हूं। वर्ष 2022 में 31,516 रेप केसेज़ रजिस्टर किए गए। जहां 86 rapes a day देश में शर्मसार करने वाली बात है और conviction rate 27.4 परसेंट ही है।

सर, यहां भ्रष्टाचार के बारे बहुत बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमने भ्रष्टाचार का corporatisation देखा है। मैं example देती हूं। मैं महाराष्ट्र से आती हूं। वहां पर post-poll alliance बनने के बाद एक चुनी-चुनाई सरकार को गिराने का काम हुआ है और उधर horse trading के लिए खुल्लम-खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों को पाला बदलवाने के लिए पब्लिक मनी को लूटा जा रहा है। के.सी. वेणुगोपाल जी कह रहे थे कि कोई एक फ्लैगशिप स्कीम बताएं, जो केंद्र सरकार ने introduce की हो। वह फ्लैगशिप स्कीम Weaponisation of ED, IT and CBI है। मैं इसलिए बोल रही हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार का corporatisation करने का काम हुआ है। ईडी के जो केसेज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए हैं, उसमें करीब चार गुना इजाफा हुआ है और 95 परसेंट अपोज़िशन पर हो रहा है। सीबीआई का भी वही हाल है। आप उसमें conviction rate देखेंगे, तो 4 परसेंट से कम है, जो यह दिखाता है कि ये politically motivated केसेज़ हैं। जो लोगों का पाला बदलवाने का काम है और जो भ्रष्टाचारी लोग इनकी साइड में आ जाते हैं, उनको वाशिंग मशीन में धो दिया जाता है। उसका weaponisation हुआ है। बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि करीब-करीब दो करोड़ रोज़गार के माध्यम बनाएंगे।...(**समय की घंटी**)... सर, मैं 30 सेकेंड्स में खत्म कर रही हूं। अब जो हालत है, तो रिकॉर्ड तोड़ unemployment है। चार करोड़ युवा बेरोजगार हैं। There is the highest unemployment in 45 years. प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी 2014 में इन्हीं चार स्तंभों की बात कर रहे थे, उनका विफल रिपोर्ट कार्ड 2024 में जनता के सामने है।

**श्री बृज लाल** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि भारत में केवल चार जातियां हैं, वे - महिला, गरीब, युवा और किसान हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, ये सब इन्हीं वर्गों पर केंद्रित हैं, क्योंकि हमारे विरोधी भाइयों को मालूम होना चाहिए कि इन्हीं चार जातियों में पूरा भारतीय समाज समाहित है। महोदय, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे पक्का मकान, शौचालय, नल से जल, उज्ज्वला गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत में पांच लाख की मेडिकल सहायता, जन औषधि केंद्र, किसान सम्मान निधि, एलईडी बल्ब और अब छतों पर सौर ऊर्जा लगाने की जो योजना चल रही है, उससे अगर सबसे ज्यादा कोई लाभान्वित हुआ है, तो गरीब हुआ है और उन गरीबों में सबसे ज्यादा एससी/एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज लाभान्वित हुआ है। मैं प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में जो एनडीए की 10 साल की सरकार है, उसमें कुछ लेजिस्लेशन पर बात करना चाहूंगा, जिन्होंने एससी/एसटी समाज को सशक्त बनाया है। पहले एससी/एसटी कानून के बारे में बात करता हूं। जब मोदी जी सत्ता में आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ खामियां हैं। तब 2015 में अमेंडमेंट शुरू हुआ और 1.1.2016 को एससी/एसटी एक्ट में अलग से 25 धाराएं जोड़ी गईं और उसको सशक्त बनाया गया। वे धाराएं क्या थीं? उसमें देवदासी प्रथा को कानूनन

अपराध बनाया गया। दलित बारात नहीं निकाल पाता था, उसको रोका जाता था। उसको कानून बनाकर अपराध बनाया। उसको बारात नहीं निकालने दी जाती थी, उसको उन्होंने सशक्त बनाया। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दलित की हत्या और बलात्कार जैसे कई मामले थे, जिसमें जहां सवा आठ लाख की एक मुश्त सहायता दी जाती है, वहां पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5,000 रुपये महीना पेंशन, टीए/डीए के साथ दी जाती है, मकान दिया जाता है, बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दी जाती है। यह सब अगर किया है, तो मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसने दलितों, आदिवासियों की दशा और दिशा बदल दी। जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि एससी/एसटी एक्ट शिथिल हुआ, तो मोदी जी कोई देरी किए बिना संविधान संशोधन लाए और उसको लाकर फिर इस कानून को सशक्त बनाया। क्योंकि हमारे विरोधी भाई लोग ऐसा प्रचारित कर रहे थे कि यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट न होकर के मोदी जी का जजमेंट है और इन्होंने कई जगह हिंसात्मक घटनाएं भी करवाईं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा लेजिस्लेशन था, जिसने दलितों को मजबूत बनाया।

दूसरा, महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है, जिससे दलित हित सीधा जुड़ा हुआ है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 है। इसका सीधा लाभ दलितों को मिला है। इसमें जो नागरिकता दी गई, वह किनको दी गई - अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश इनसे जो प्रताड़ित होकर हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन ये सब आए। महोदय, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए थे, वे दलित थे। मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा, एक जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, वे दलित थे, वे बाबा साहेब के सहयोगी थे। वे कंबाइंड बंगाल में सुहरावर्दी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे। जब 1946 में इंटेरिम गवर्नमेंट नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, तो वे अविभाजित भारत के लॉ मिनिस्टर थे।

महोदय, उसके बाद जब देश विभाजित हुआ, तो मंडल जी ने कहा कि हमारे दलित, जो इस्लामिक देश पाकिस्तान बन रहा है, वहां पर सुरक्षित रहेंगे और इनकी वजह से जो दलित थे, वे वहां रुक गए। लेकिन काफ़िर और कुफ्र की बुनियाद पर बनी इस्लामिक कंट्री, उसमें जो अत्याचार होना था, वह हुआ और जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ, वह दलित हुआ, क्योंकि वे मंडल जी की वजह से वहां पर रह गए थे। जिन्ना ने उनको पाकिस्तान का लॉ और लेबर मिनिस्टर बनाया था। महोदय, वे वहां पर गए और 8 अक्टूबर, 1950 को इस्तीफा देकर भाग आए थे और जब वे भाग आए, तो दलितों में भगदड़ मची और उनको असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश और बिहार में बसाया गया। वे नमो शूद्र और मतुआ थे। महोदय, सीएए में जो नागरिकता मिली, उसमें 70 से 75 परसेंट दलित थे, जिनको मोदी सरकार ने नागरिकता दी और नागरिकता मिलने पर जो तमाम सुविधाएं थीं, जिनसे वे वंचित थे, वे उनको मिलीं। यह काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया, इसलिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, जिन्होंने दलितों की दशा और दिशा बदल दी। इसका विरोध कौन कर रहे थे, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कर रही थी। दिल्ली के शाहीन बाग में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जाकर हाजिरी देते थे और यह किससे प्रायोजित था? यह पीएफआई, आतंकवादी संगठन द्वारा प्रायोजित था और वहां पर दलितों को भ्रमित किया जाता था। बाबा साहेब का फोटो, संविधान, देश का तिरंगा लेकर के इन्होंने विरोध किया। किसका विरोध किया? यह दलितों का विरोध किया, चूंकि जो नागरिकता मिली, वह 70 से 75 परसेंट दलितों को मिली।

महोदय, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन हुआ, वह हुआ आर्टिकल 370 को हटाने का। आर्टिकल 370 जब था, तो वहां पर दलितों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, कोई आरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि जो भी कानून बनता था, उसमें कहा जाता था कि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर। जब धारा 370 को हटाया गया, तब वहां के लोगों को अधिकार मिला और उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं। ...(**समय की घंटी**)... अभी कल ही जम्मू-कश्मीर के लिए कानून पास हुए हैं। महोदय, मैं एक मिनट का समय और चाहूंगा। उन कानूनों के माध्यम से मोदी सरकार ने दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देकर उनको सम्मान दिया है, यह मोदी सरकार ने किया है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार में तमाम लेजिस्लेशन पास हुए हैं और उनके माध्यम से सरकार ने दलितों की दशा और दिशा बदल दी है। इस कार्य का हमारी विरोधी पार्टियां हमेशा विरोध कर रही थीं, दलितों का विरोध कर रही थीं, बाबा साहेब को सम्मान मोदी सरकार ने दिया है, पंचतीर्थ मोदी सरकार ने बनाए हैं, कांग्रेस सरकार बाबा साहेब को भारत रत्न से वंचित कर रही थी, उनको बीजेपी के इंटरवेंशन के कारण भारत रत्न मिला। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं बताना चाहता था कि जो तमाम लेजिस्लेशन्स बने, उनमें ये तीन-चार मुख्य लेजिस्लेशन्स हैं, इनमें दलितों का हित सीधा जुड़ा था, जिसको मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया, धन्यवाद।

**श्री उपसभापतिः** धन्यवाद बृज लाल जी। श्री रामदास अठावले जी।

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले):** उपसभापति महोदय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में जो घोटाले हुए, उनका व्हाइट पेपर आज यहां हाउस में पेश किया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि, "This Paper is White because this time is right. This is Congress Party's Night, and, against corruption, always we fight." हम लोग करप्शन के विरोध में हमेशा काम करते हैं। सत्ता में कोई भी हो, उन्हें घोटाले नहीं करने चाहिए, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवैल्थ घोटाला हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण जी व्हाइट पेपर लाने वाली मंत्री हैं, इसलिए हम सभी लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चहिए। जो काला धन है, उससे सरकारी खजाने में पैसा नहीं आता है, इसीलिए डेवलपमेंट के काम के लिए भी पैसा नहीं रहता है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत देश बहुत ही खुशहाली से आगे बढ़ रहा है। देश के अंतिम वर्ग को न्याय दिलाने के लिए - वह चाहे गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगिरी के लोग हों, उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार काम करती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि,

*"कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत हुआ था भ्रष्टाचार*
*इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने किया है उस पर वार।*
*कांग्रेस पार्टी की 2024 में हो जाएगी हार*

*और उस वक्त बीजेपी ने किए थे 282 पार।"*

महोदय, बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें जीती थीं। जनता जिनका साथ देती है, उनको सत्ता मिलती है। कांग्रेस पार्टी को भी साथ मिला था। जयराम रमेश जी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के बाकी लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको व्हाइट पेपर पर चर्चा नहीं करनी है। उन्होंने चर्चा में थोड़ा भाग लिया है। ..(**समय की घंटी**)..कांग्रेस के लोग यहाँ मौजूद नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि,

*'हम नहीं डरेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे।'*
*हम नहीं डरेंगे विषमता को खत्म करेंगे।'*
*हम नहीं डरेंगे, हम काम करेंगे।*

..(**समय की घंटी**)..

**श्री उपसभापतिः** माननीय रामदास अठावले जी, आपका समय खत्म हो गया है।

**श्री रामदास अठावलेः** उपसभापति जी, यहाँ हाउस में जो व्हाइट पेपर लाया गया है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, हमने दस साल में क्या किया है - इनके संबंध में भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गरीबों को न्याय देने वाली सरकार है। ..(**समय की घंटी**)..

**श्री उपसभापतिः** माननीय रामदास अठावले जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप एलॉटिड समय से अधिक बोल चुके हैं।

**श्री रामदास अठावलेः** मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। उनके दस साल के कार्यकाल में जो अनियमितताएं हुई हैं, इस व्हाइट पेपर में उसका लेखा-जोखा देना चाहिए।

**श्री उपसभापतिः** माननीय रामदास अठावले जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अब मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। घनश्याम तिवाड़ी जी, आप बोलिए, आपका समय शुरू हो रहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (राजस्थान)**:** माननीय उपसभापति महोदय, इस श्वेत पत्र पर जो चर्चा चल रही है, वह केवल अर्थव्यवस्था के विकास की चर्चा नहीं है, बल्कि इस श्वेत पत्र को पढ़ने के बाद, यह चर्चा हमें साथ-साथ यह भी इंगित कर रही है कि यह चर्चा भ्रष्टाचार बनाम विकास की चर्चा है। पिछला दशक, जो कांग्रेस पार्टी का रहा, वह अव्यवस्था, अनाचार और भ्रष्टाचार का रहा और जो माननीय नरेन्द्र मोदी का दशक रहा, यह दशक भारत की प्रगति, भारत के पराक्रम और भारत के पौरुष का है। अगर इसमें हम देखेंगे, तो हमें कुछ बातें साफ नज़र आएंगी। चाणक्य ने कहा था कि वह राज किस काम का, जो राज आम जनता के लिए काम नहीं कर सके। उन्होंने यहां तक

लिखा कि यदि अकाल पड़ जाए, तो राजा जिस मकान में रहता है, उसको भी बेचकर जनता की सेवा करे। उन्होंने कहा - सुखस्य मूलं राज्यं, राज्यस्य मूलं धर्मः। मोदी जी ने इसे चरितार्थ किया कि जब हमारे यहां कोरोना काल आया, उस समय 2 अरब से ज्यादा लोगों को 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इस प्रकार का जन कल्याण का काम किया, तो जन कल्याणकारी सरकार किसे कहते हैं, उस जन कल्याणकारी सरकार का काम इसमें प्रदर्शित हुआ। आप अर्थव्यवस्था में देखें, पहले यह दसवीं अर्थव्यवस्था थी और बहुत मेहनत करके 10 वर्ष में उसको पांचवीं अर्थव्यवस्था बनाया, यह काम मोदी जी ने किया।

माननीय उपसभापति महोदय, वह पैसा किस काम का जब कोई कहे कि राज्य के पास पैसे हैं, लेकिन राज्य में रहने वाले आदमी के आरोग्य का साधन नहीं है, दवाई का साधन नहीं है। हम बचपन में सुना करते थे, हम जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी थे, हम डा. लोहिया जी के आंदोलन में भी थे, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आंदोलन में भी थे और एक ही नारा लगाया करते थे - रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान। यह नारा बहुत वर्षों तक लगाया गया, लेकिन इस नारे को यथार्थ करने का काम इस दशक में किया गया। रोटी चाहिए, तो 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन मुफ्त दिया गया, जबकि पहले क्या था - राशन में भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा भी दिया गया और मकान चाहिए, तो 4 करोड़ लोगों को मकान बनाकर दिए गए। यह सरकार की लोकतांत्रिक सोच और अर्थव्यवस्था की वृद्धि का सूचक है। हम जब पिछले दशक में थे, तो भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले निरंतर गिर रहा था और भारत की साख इंटरनेशनल एजेन्सीज़ में बहुत कम हो गई थी। विदेशी मुद्रा का भंडार 303 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अब 617 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ऐसा निरंतर होने वाली प्रगति के कारण है। 2004 में देश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज थे? सब लोग बाहर जाते थे। अब भी कुछ जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, चाहे वह मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे अन्य पढ़ाई हो। कांग्रेस पार्टी ने ही सैम पित्रोदा जी के नेतृत्व में एक आयोग बनाया था। उन्होंने कहा था कि भारत में कम से कम 1,500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, लेकिन इन्होंने तो नहीं बनाए। इस दशक में 1,467 से अधिक विश्वविद्यालय भारत में हो गए हैं। हमारे यहां विदेशों से बहुत से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। शिक्षा की नई नीति लागू की गई है। उसके लिए जो खर्चा करना चाहिए, वह लगातार करते जा रहे हैं। इस अर्थव्यवस्था को, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, इसको कमजोर करने के लिए - मैं आरोप लगाना चाहता हूं - बार-बार विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र किया गया। एक विदेशी अरबपति जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग जैसी एजेन्सीज़ ने जान-बूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्होंने षड्यंत्र रचकर कुछ कागज बनाए। उन कागजों को लेकर यहां पर सदन में कांग्रेस के लोगों ने पूरे का पूरा सत्र समाप्त कर दिया।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

अडाणी-अडाणी पुकारते रहे और उस अडाणी-अडाणी के अंतर्गत, भारतवर्ष के हज़ारों शेयरहोल्डर्स ने, जिन्होंने अडाणी की कंपनी में पैसे लगाए थे, उनका पैसा शेयर में कम हुआ और हज़ारों लोगों को नुकसान हुआ।

2.00 P.M.

इस पाप की भागीदार अगर कोई है, तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने हजारों व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाया। आपने जाँच करा ली, सुप्रीम कोर्ट की जाँच हो गई, सेबी की जाँच हो गई, सारी जाँच हो गई और जाँच में आपके सारे आरोप गलत लगे, लेकिन आपके नेता तो अडाणी-अडाणी करते रहे। भारत में और भी बहुत कुछ है, भारत आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा दुनिया के किसी और देश में होता, तो उसके उद्योगपतियों के बारे में पढ़ाया जाता, उनका सम्मान किया जाता। इस बार जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसमें माननीया वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसका भी हमको बहुत बड़ा काम है। आईटीआई के संस्थान खुले। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Jairam *ji*, I decide when time is over. You don't decide it. Your right*...(Interruptions)...* I have seen this morning. Don't compel me. I have seen all the rights in this House today. *...(Interruptions)...* Your right, your duty and responsibility of the Members of the House and what we need to do. Please continue, hon. Member.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी:** माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़ रही है ...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी:** उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर घातक प्रहार करने का काम प्रतिपक्ष ने किया। आज का उनका जो व्यवहार दिख रहा है, उनकी उपस्थिति दिख रही है, वे इस भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखना नहीं चाहते। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि मेरे तीसरी बार आने के बाद भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, उस समय पॉलिसी पैरालिसिस था। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ। राजस्थान में अभी चुनाव संपन्न हुआ है। ईआरसीपी का बहुत दिनों तक मामला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। अभी नई सरकार बनी और ईआरसीपी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत, ट्रिपल इंजन की सरकार ने मिल कर उस काम को पूरा कर दिया। अभी एक काम और बाकी है। सभापति महोदय, वह काम आपका है और उसमें आपका भी नाम है। शेखावाटी में बहुत वर्षों से एक काम पेंडिंग है। वह जो काम पेंडिंग है, उसमें यह है कि आज से 30 वर्ष पहले यह फैसला हो गया था कि गंगा-यमुना के फ्लड वॉटर से, हथिनी कुंड से सीकर, झुंझुनू और चुरू को 1,920 क्यूसेक पानी मिलेगा। यह पानी मिलने की बात तो हो गई, लेकिन आज तक उन्होंने इसे होने नहीं दिया। अब इसकी बात शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्य मंत्री से भी मिल लिए हैं, सुजला शेखावाटी समिति उसमें काम कर रही है, गजेन्द्र सिंह शेखावत जी से भी मिल लिए हैं और हरियाणा के मुख्य मंत्री से भी मिल लिए हैं। तीनों के मिलने से अब मुझे

आशा है कि निश्चित रूप से जल्द ही वह काम भी हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, वहाँ एक कहावत है, मैं आपको याद दिला दूँ, यह आपकी कहावत है कि शेखावाटी में कौन-कौन रहते हैं। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन 'जन में जाट और जंगल में जाटी', मतलब जो जन, आदमी हैं, उनमें जाट ज्यादा रहते हैं और जंगल में खेजड़िया जो जाति है, वह ज्यादा रहती है। जन के जो जाट हैं, उनके लाभ के लिए और जो खेजड़िया हैं, उनके लाभ के लिए यह यमुना का पानी आ जाएगा, तो ठीक होगा।

सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख है कि आज जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने आसन का अपमान किया है, चेयर का अपमान किया है, वह आसन और चेयरमैन का नहीं, इस सदन का अपमान है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, more than calling this a White Paper on Indian Economy, I would call it a White Paper on Upcoming Elections. While the Government pats its own back on the growing economy and hits out at the opposition, it refuses to look at the ground realities. Two things that the Government must be praised for, in any case, are: setting effective narratives and excellent event management. सर, हिन्दी में एक गाना था,

*"चाँदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया,*
*इस धनवानों की सरकार ने निर्धन का दामन छोड़ दिया।"*

† چاندی کی دیوار نہ توڑی پیار بھرا دل توڑ دیا
اس دھنوان کی سرکار نے نردھن کا دامن چھوڑ دیا

Sir, inequality in India is at obscene levels.While still home to a very large number of people living in destitution, the number of dollar billionaires in India has increased. Our White Paper speaks nothing about the impact of the economy on the people which is a part of the title; it does not speak about widespread unemployment; it does not speak about rising prices; it does not speak about crimes against women; it does not speak about corruption. Corruption is on the rise but what can be done if the Government refuses to see it from the point of the view of the common man? Go to a police station, go to a Tehsil, go to any Education office, etc., you will see corruption

† Transliteration in Urdu script.

there. How can you say that there is no corruption when the common man experiences it every day in his life? *

MR. CHAIRMAN: Madam, one second please! We cannot name someone. That will not be a part of record.

DR. FAUZIA KHAN: Sorry!

MR. CHAIRMAN: Under the rules, we cannot level an allegation against someone who is not a Member of the House.

DR. FAUZIA KHAN: I am not levelling any allegation. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am cautioning. ...*(Interruptions)*...

DR. FAUZIA KHAN: I am asking. ...*(Interruptions)*... I am not levelling allegations. This is not an allegation. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is fact may be allegation also. ...*(Interruptions)*... We never know. ...*(Interruptions)*... I don't want to make an issue of it. ...*(Interruptions)*... Please continue.

DR. FAUZIA KHAN: I am only asking a question as to how does a person become clean in two days.

MR. CHAIRMAN: That part will not go on record. That I will check. Please continue.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I am talking about NCRB statistics about farmers. According to NCRB statistics, there are 30 farmers who commit suicides every day. On the 19th of September, 2022, a farmer from Pune, Mr. Dashrath Lakshman Kedari, left a suicide note wishing birthday greetings to the Prime Minister. Near my hometown, in Gangakhed, in my district, one farmer committed suicide saying, "Tomorrow please come for my अन्तिम संस्कार". Can't we see the tears of these farmers or we will only be satisfied by giving them *samman*? सर, हाथी के दाँत दिखाने के और हैं, लेकिन खाने के और हैं। Is this Ram Rajya where the seeds of hate are sown? Is this Ram Rajya where

* Expunged as ordered by the Chair.

bulldozers are used to demolish houses of poor people? Is this Ram Rajya where mob lynching takes place? Is this Ram Rajya जहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर शूटिंग होती है? I want to ask. I will just end with one couplet:

*"मकड़ी के जाले की तरह वह टूट कर ही रह गया,*
*जिसकी बात में यहाँ झूठ की मिलावट हो।"*

†مکڑی کے جالے کی طرح وہ ٹوٹ کر ہی رہ گیا
جس کی بات میں یہاں جھوٹ کی ملاوٹ ہو

धन्यवाद, सर।

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Mr. Chairman, Sir, I thank you for providing me this opportunity to share my thoughts on the White Paper which the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharman, has presented in the Parliament. Before I share my thoughts, I just want to mention 2-3 things which I feel are relevant to the subject. Already I have mentioned once that the first railway station which the State of Nagaland got was in 1903. You will be surprised to know that for the second railway station, the North-Eastern people had to wait for long 119 years! It is only after Modiji's Government in 2023 that we got the second railway station in the State of Nagaland.

Sir, another point is related to development. The foundation stone of the longest rail-cum-road bridge, that is, Bogibeel Bridge, was laid in the year 1997 by the then hon. Prime Minister, Devegowdaji. But the construction began in 2002 under the guidance of *Param Adarneeya* Atal Bihari Vajpayeeji. You will be surprised to know that it was about to break the record time for construction of Taj Mahal. It took 21 years to complete it! Only after Narendra Modiji took charge as Pradhan Sewak and after 21 years, the Bogibeel Bridge was operational._So, once our hon. former Prime Minister Devegowda*ji* asked me in the old Parliament House that whether the people of Assam remember him. I said: "Yes, Sir. People of Assam and the North-East always fondly remember you and hon. former Prime Minister Vajpayee*ji*." सर, जब remember की बात की, तो we also remember *Param Adarniya* Nehru*ji* also who, in 1962 Chinese aggression, surrendered saying, "My heart goes with the people of Assam." We also remember *Param Adarniya* Indira Gandhi*ji* under whose instructions the first airstrike was carried out in the own civilian territory of India. खुद के राष्ट्र के

† Transliteration in Urdu script.

अंग, Mizoram में बमबारी की गयी थी। It is the first and last instance. We fondly remember Manmohan Singh*ji* also. We respect him. He is one of the best luminaries in the field of economics and public administration. We, the Assamese people, sent him to this august House for two-three times from Assam. After coming here, he occupied the most honourable post, that is, Prime Ministership of our country. But, during his tenure, he visited there only eight to nine times. We sent him with pride but he visited there during those ten years only eight to nine times. But our Pradhan Mantri *Param Adarniya* Narendra Modi*ji* has visited Assam and the North-East for 65 times. This is the difference! We remember him that's why. We remember *Adarniya* Rahul Gandhi*ji* also who in 2022 February officially reiterated in a statement about his concept about India. I have already mentioned once here in this august House that his concept of India is from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Bengal. In his concept of India, there is no North East. We remember him also. We remember hon. the Leader of the Opposition, *Param Adarniya* Kharge*ji* also. He is a statesman in politics. When Congress Party was very badly defeated in the Assembly elections of Tripura and Nagaland and when the media asked him, he replied -- 'one can search on the internet, छोटा-छोटा राज्य है, it doesn't impact', the way he underestimated the people of North-East. This reflects what? उन लोगों के लिए असम में कितनी सीट्स हैं, त्रिपुरा में कितनी सीट्स हैं, they judge, they love, they estimate a State by the number of Lok Sabha seats. But खरगे जी हों या काँग्रेस, मैं यही बताता हूँ कि नॉर्थ-ईस्ट में एक-एक को मिला कर कुल 25 सीट्स हैं और इस बार वे सारी 25 सीट्स मोदी जी की तरफ ही आ रही हैं, because, Modi*ji* considers North-East to be the growth engine of modern India. Thank you, Sir.

**डा. सिकंदर कुमार** (हिमाचल प्रदेश): सर, आपने मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मान्यवर, विभिन्न वैश्विक दबावों और चुनौतियों के बावजूद जिस कुशल वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नियोजन का मोदी सरकार ने परिचय दिया है, उसके लिए मैं मोदी सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह बेहतर आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय नियोजन का ही परिणाम है कि आज भारत में देखें, तो हर क्षेत्र में, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

मान्यवर, अगर हम पूरे विश्व की 7 top world seven economies की बात करें, तो उन 7 top world seven economies में अगर सबसे बढ़िया growing economy कोई है, तो वह हमारे देश, भारत की है, जो 7 per cent से ज्यादा grow कर रही है। यह आर्थिक नियोजन का ही परिणाम है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो अगर किसी देश की cost of living बेहतर

है, तो वह हमारे देश, भारत की है। हम चाहे cost of construction की बात करें, cost of consumption की बात करें, cost of energy की बात करें। अगर हम पिछले 7-8 वर्षों के आँकड़ों को देखें, तो यह पता चलेगा कि हमारे देश में investment growth लगातार बढ़ रही है, Bank credit growth लगातार बढ़ रही है। अगर मैं 2014 की बात करूँ, तो उस समय भारत का foreign reserve 304.2 बिलियन डॉलर था और आज 2024 में यह double होकर 618.94 बिलियन डॉलर हो गया है। यह बेहतर आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है, यह मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है। मान्यवर, अब मैं monthly gross GST-collection की बात कहना चाहूँगा कि Financial Year, 2018 में हमारे देश में यह 0.9 लाख करोड़ थी, जो आज 2024 में बढ़कर 1.7 लाख करोड़ हो गया है। जहाँ तक inflation की बात है, तो वर्ष 2014 में inflation rate 9.4 परसेंट था, वहीं आज वर्ष 2024 में वह घटकर 5.5 परसेंट रह गया है।

सर, जो Gross Non-Performing Assets हैं, as a percentage of gross advances वर्ष 2018 में 11.2 परसेंट थे, वहीं सितम्बर, 2023 में ये घटकर 3.2 परसेंट रह गए हैं। जैसा कि विपक्ष के लोग कह रहे थे कि unemployment का क्या हुआ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2017-18 में इस देश का unemployment रेट 6.1 परसेंट था, वह वर्ष 2022-23 में घटकर 3.2 परसेंट हो गया, जो यह दर्शाता है कि मोदी जी की नीतियों की वजह से देश में किस प्रकार से unemployment घटा है। जहाँ तक current account deficit as a percentage of GDP की बात है, तो यह वर्ष 2014 में लगभग 2 परसेंट था, वह आज 2024 में घटकर लगभग 1 परसेंट हो गया है, जो कि हमारी बेहतर आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यहाँ कुछ आँकड़े रखना चाहता हूँ, जो दर्शाते हैं कि वे वर्ष 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार और वर्ष 2014 से 2024 के बीच में एनडीए की सरकार में क्या अंतर है। देश का GDP, जो वर्ष 2004 और 2014 के बीच में 98 लाख करोड़ था, वह वर्ष 2015 और 2023 के बीच में बढ़कर 159.7 लाख करोड़ हो गया। यह भी यही दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वह वर्ष 2004-2014 के बीच में जहाँ 86,454 रुपये थी, वहीं आज 2024 में वह बढ़कर डेढ़ लाख से ऊपर पहुँच गई है। यह मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। आयकर दाता, जो वर्ष 2004-2014 के बीच में 3 करोड़ 80 लाख थे, आज वे बढ़कर 6 करोड़ 70 लाख, अर्थात दोगुने हो गए हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, दो मिनट। मेरी यह maiden speech है।

MR. CHAIRMAN: Two minutes is too long. Your original time was four minutes only.

DR. SIKANDER KUMAR: Sir, one minute!

MR. CHAIRMAN: Thirty seconds, conclude.

**डा. सिकंदर कुमारः** सर, वर्ष 2004-14 के पीरियड में Defence Exports 1,941 करोड़ था, जो आज बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में जहाँ 10वें स्थान पर

थी, वह आज पाँचवें स्थान पर आ गई है और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी की तीसरी टर्म में यह वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Vijay Pal Singh Tomar; seven minutes.

**श्री विजय पाल सिंह तोमर** (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी और उनकी सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कल चौधरी चरण सिंह जी, डा. एम.एस. स्वामीनाथन जी और पी.वी. नरसिम्हा राव जी को 'भारत रत्न' देने की घोषणा की और इससे पहले यह सम्मान डा. कर्पूरी ठाकुर जी को दिया।

दूसरा, इससे पहले जब 10 साल की यूपीए की सरकार आई थी तो उससे पहले देश की आर्थिक स्थिति ठीक थी, क्योंकि अटल जी की सरकार ने उन्हें देश को सही स्थिति में सौंपा था, लेकिन वह सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जानी गई। उस पूरी सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले हुए। उसके कारण क्या थे? सर, 50 साल में बैंकों से जितना ऋण दिया गया, लगभग उतना ही ऋण इन्होंने 8 साल में दे दिया, डिफॉल्टर्स को भी दे दिया, बिना किसी गारंटर के भी दे दिया और ऐसे लोगों को दे दिया जो लेकर भाग गए। अब उनसे मोदी जी वसूल कर रहे हैं, उनसे पाई-पाई वसूल की जाएगी। इन्होंने दिया और उनसे वसूल करने का काम मोदी जी को सौंपा। तब बजट से ज्यादा कर्जा हो गया, यह स्थिति उस सरकार की थी। उस समय बैंक ठप होने जा रहे थे और एक अपंग की तरह काम किया जा रहा था, क्योंकि उसी समय कोयला घोटाला भी हुआ। अभी कई लोगों ने बताया, कोल ब्लॉक आवंटन में 1 लाख 86 हज़ार का घोटाला हो गया, राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला हो गया, 2जी टेलिकॉम स्पेक्ट्रम में 1 लाख 76 हज़ार का घोटाला हो गया, शारदा चिट फंड में घोटाला हो गया, आदर्श सोसायटी घोटाला हो गया, हॉक विमान खरीद घोटाला हो गया, आगस्तावैस्टलैण्ड हेलिकॉप्टर्स घोटाला हो गया। वह घोटालों ही घोटालों की सरकार थी। हम जब भी सोचते थे, जब हमें हर महीने कोई खबर आती थी तो एक घोटाला सामने आ जाता था। वर्तमान सरकार जब से आई है, तब से भारत डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। महोदय, यहां यूपीए के समय महंगाई दर लगभग 8 प्रतिशत थी और इससे ऊपर ही रही जबकि एनडीए के टाइम में 5 प्रतिशत से ऊपर कभी नहीं गई। वर्ष 2004 से 2014 के बीच ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छता पहली जरूरत थी और इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर इस बात को cover करने का काम किया। स्वच्छता के अलावा यहां प्रति व्यक्ति आय दस वर्ष में दोगुनी हो गई है। यूपीए के टाइम में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी, लेकिन एनडीए के टाइम ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, जो 100 वर्षों में कभी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी 222 करोड़ को free vaccine doses देने के बावजूद, 80 करोड़ से अधिक लोगों को free ration देने के बावजूद भी, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछली दो छमाही में भारत की आर्थिक विकास दर की वृद्धि 7.6 per cent हो रही है, जबकि China 4.6 per cent पर है, अमरीका भी - ये सब हमसे पीछे हैं। आज हम एनडीए की सरकार में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए हैं और मोदी सरकार का संकल्प है कि 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसका

क्या कारण है? इसका कारण यह है कि आज पारदर्शिता से, ईमानदारी से सब काम हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है जो कि 1.97 लाख प्रति व्यक्ति सालाना है। मैं यहां यह जरूर बताना चाहूंगा, कल से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, कांग्रेस के एक नेता ने कुछ ऐसे आंकड़े दिए कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान की स्थिति इतनी खराब हुई है। जब मैं 2013-14 में आया, तो Agriculture Ministry में एक meeting हुई थी। वहां मैंने पूछ लिया कि crops से net income क्या है? तब वहां के अधिकारियों ने बताया कि crops से net income 6,324 रुपये सालाना है। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा कि इसमें दूध नहीं माना जाएगा, यदि कोई बाहर से इन्कम हो रही है, तो उसको नहीं माना जाएगा, तो प्रति माह income 527 रुपये हुई। यह मजदूर से नीचे किसान को लाकर किसने खड़ा किया? 54 per cent जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, तो वे किसके कारण नहीं थे? 50 साल तक राज तो उन्होंने किया था, तो क्यों इन वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया? इन्होंने किसान को मजदूर से नीचे लाकर खड़ा कर दिया और अब बात कर रहे हैं! मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी नहीं, ढाई गुनी की। वे 500 रुपये महीना तो किसान सम्मान निधि में देने का काम कर रहे हैं। 11 crore से अधिक किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, 2,80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा दे दिए और यही नहीं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों - मैं एक-दो बातें इसमें जरूर कहूंगा। इनके दस साल में यूपीए का जो कृषि का बजट था, वह 1,48,162 करोड़ था, जबकि NDA के टाइम पर यह 6,21,940 करोड़ रुपये है। यूपीए का आखिरी पांच वर्ष का जितना बजट था, उससे अधिक एक वर्ष का पिछले साल का NDA का बजट है जो कि 1,25,000 करोड़ रुपये का है।

महोदय, मैंने आपको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बताया। eNam की मंडी-1,389 मंडियां काम कर रही हैं। कल फसल बीमा के बारे में बहुत बात उठा रहे थे, और भी कई लोगों ने उठाई, तो कुल 56.97 करोड़ नामांकित आवेदन आए, जिनसे किसानों के खाते में बीमे का 1,54,498 करोड़ रुपया सीधे गया है। महोदय, यही नहीं, जब कल बात कर रहे थे और वे कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो वे कह रहे थे कि एमएसपी पर खरीद नहीं हुई। उस पर कितनी खरीद हुई, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। महोदय, 2004-05 से लेकर 2013-14 तक इन्होंने 2,84,000 करोड़ रुपये के धान की खरीद की और भारतीय जनता पार्टी की या NDA की सरकार ने 12,14,000 करोड़ रुपए की खरीद की। इनसे छह गुनी खरीद की। इन्होंने 2,54,000 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद की है और हमारी सरकार ने 5,05,000 करोड़ रुपये की खरीद की है। वे दलहन की खरीद पर बहुत जोर दे रहे थे। उनकी कुल खरीद 1,936 करोड़ रुपये की थी और हमारी सरकार की 85,908 करोड़ रुपये से ऊपर की थी। महोदय, MSP पर भी खरीद की। उनकी तिलहन की खरीद 10 साल में 10,261 करोड़ रुपये की थी, हमारी 34,055.79 करोड़ रुपये की है। महोदय, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तो वर्ष 2006 में आ गई थी, आपने क्यों लागू नहीं की थी? हमने उसको लागू किया, लागत का डेढ़ गुना भी दिया और खरीदारी करने का काम भी किया।

महोदय, इनके समय में सॉइल हैल्थ कार्ड नहीं थे, हमने 23 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हैल्थ कार्ड बांट दिए। टैस्टिंग लैब्स 171 थीं, जो हमारे समय में बढ़कर 12,108 हो गईं। इस तरह से हर क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने का काम किया। आज किसानों के लिए तेज़ी से काम किया गया है।

महोदय, आज जब जयंत चौधरी जी खड़े हुए और कांग्रेस बेंचों से हंगामा हुआ, तब मुझे एक बात याद आई। वर्ष 1967 में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ लोगों में कुछ नाराज़गी हुई थी, तब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग नारे लगा रहे थे, कोई कहता था कि खा गए राशन, पी गए तेल - यह देखो कांग्रेस का है। सर, शामली के पास शोरम गोला में एक पंचायत हो रही थी, वहां जो भी खड़ा हो रहा था, वह कांग्रेस की बुराई कर रहा था। एक ताऊ झगड़ू थे, उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ कहूंगा। उनसे कहा गया कि कहो, वे बोले कि सब लोग बुराई कर रहे हैं, एक गुण भी तो है, पूछा गया कि वह क्या है, तो बोले कि इन सब बातों के बावजूद भी ये शर्माते नहीं हैं। इन्होंने किसानों की स्थिति खराब की, उसके बाद भी शर्माते नहीं हैं। यदि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, तो सब विरोध करने के लिए खड़े हो गए। क्या आप उसका विरोध करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपने तो उनको भारत रत्न नहीं दिया। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने किसी एक परिवार को नहीं दिया, बल्कि किसानों को 'पद्मश्री' दिया, 'भारत रत्न' उन लोगों को दिए, जिनको मिलने चाहिए थे। मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वर्तमान सरकार ने 'उज्ज्वला योजना' के तहत 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देने का काम किया, विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014 में 723 थी, जो अब 1,113 से ऊपर है। डिग्री कॉलेजेज़ 5,298 थे, जो अब 43,796 हैं। 7 नए आईआईएम्स बने, 7 नए आईआईटीज़ बने, 225 नए मेडिकल कॉलेजेज़ बने हैं, ...(**समय की घंटी**)... 8 All India Medical Institutes थे, जो बढ़कर अब 23 हो गए हैं। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैंने कल भूतल परिवहन मंत्रालय के बारे में कहा कि इनके समय में आखिरी साल का बजट 34 हज़ार करोड़ रुपये से कम का था, हमारा बजट 2 लाख 70 हज़ार 435 करोड़ रुपये का बजट रहा। ये 12 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे थे, हम 29 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे हैं।

**श्री सभापतिः** श्रीमती सीमा द्विवेदी।

**श्री विजय पाल सिंह तोमरः** मान्यवर, मैं एक सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने रेलवे के 21,000 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया था, हमने 58,424 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया है। इनके समय में स्टार्टअप्स नहीं थे, हमारे समय में 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हैं। मोदी जी की सरकार ने इन 10 वर्षों में हर क्षेत्र में अद्भुत काम किए हैं, इसीलिए घोटालों की सरकार को जनता ने नकारा और आगे बीजेपी 400 पार होने जा रही है।

**श्रीमती सीमा द्विवेदी** (उत्तर प्रदेश)**:** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। वर्ष 2014 में जनता ने मोदी सरकार को बागडोर संभालने के लिए भारी जनादेश दिया। विरासत में मोदी जी को कमज़ोर भारत एवं बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई। डिजिटल क्रांति से लेकर खुले में शौच उन्मूलन, काले धन का पता लगाना एवं भ्रष्टाचार को रोकना मोदी जी की नीति एवं नीयत को दर्शाता है। 10 वर्षों में कई दिग्गज देशों को पीछे धकेलते हुए भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। महोदय, अगर कोरोना महामारी न आई होती, तो दो-तीन साल पहले ही हमारा देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया होता। आधार की उपयोगिता ने डीबीटी के माध्यम से 1.167 करोड़ लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ से

अधिक सुविधा दी। 'स्वच्छ भारत मिशन', 'उज्ज्वला योजना', 'पीएम जनधन खाता', 'पीएम किसान सम्मान निधि', 'श्री अन्न योजना', बिजली, एयरपोर्ट्स, एनएचएआई, 'पीएम आवास योजना', 'पीएम विश्वकर्मा योजना', 'लखपति दीदी', 'बैंक सखी', 'ड्रोन सखी', 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और अंत में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लाकर महिलाओं को शून्य से शिखर पर पहुंचाने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया।

महोदय, अब मैं यूपीए सरकार के कुछ घोटालों के बारे में बताना चाहती हूं। यूपीए सरकार घोटाले की सरकार थी, क्योंकि उनकी नीति एवं नीयत, दोनों में खोट थी, घोटाले पर घोटाला - मान्यवर, हम जब प्राइमरी में पढ़ते थे, तब हमको पहाड़ा पढ़ाया जाता था, वैसे ही मैं इनके घोटालों के बारे में बताना चाहती हूं। शारदा चिटफंड घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, मीडिया घोटाला, नौकरी के लिए भूमि घोटाला, कोयला घोटाला - कोयला घोटाला के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने इनके कोयले आवंटन को रद्द करके इनके घोटाले पर मुहर लगाने का काम किया था। यह भी सबकी जानकारी में होगा। जुलाई, 2012में हुई बिजली की कटौती इतिहास में सबसे बड़ी कटौती थी। पूरा देश अंधेरे में था, आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। यूपीए की सरकार के मंत्री जेल में गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। महोदय, माननीय मोदी जी के आने के बाद बिजली में बहुत परिवर्तन आया है। आज गांव में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। अब हम 2014 तथा 2014 के बाद के भारत की तुलना करते हैं। हमारे देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद से कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस देश के प्रधान मंत्री जी का संकल्प है। महोदय, कांग्रेस कहती थी - देश चाहे रहे या न रहे, मेरी सरकार और मेरा परिवार रहना चाहिए, परन्तु मोदी जी कहते हैं, मैं रहूं या न रहूं, सरकार रहे या न रहे, मेरा देश रहना चाहिए। महोदय, यह हमारे प्रधान मंत्री जी का संकल्प है।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश में यदि राम मंदिर का निर्माण हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजे, उनको प्रतिष्ठित किया गया, जिनकी वजह से करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की मंशा पूरी हुई। महोदय, सरयू नदी का पानी खून से लाल था। कोठारी बंधुओं सहित तमाम कारसेवकों पर गोलियां चलाई गईं। यह दिल को झकझोर देती था, जब कोठारी बंधुओं की माँ ने यह कहा कि अगर मेरा कोई तीसरा बेटा होता, तो उसको भी मैं कारसेवा के लिए भेज देती।

महोदय, आज करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों का मन खुश हुआ है, क्योंकि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बना है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार द्वारा काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर, मिर्जापुर विंध्य कॉरिडोर, मथुरा में मंदिरों का निर्माण करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विकास को गति मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी।

महोदय, कांग्रेस के जमाने में, हमको याद है जब इनकी सरकार थी, तो सड़ा लाल गेहूं ये बाहर से खरीद कर लाते थे और कोटे की दुकानों में रखकर बेचते थे। महोदय, सबने देखा होगा कि कोटे की दुकान पर राशन लेने पर लाठीचार्ज होता था, आज हमारी सरकार लगातार निशुल्क राशन दे रही है और आगे देती भी रहेगी। हमारी सरकार वन नेशन, वन राशन कार्ड देश के लिए लाई है, जो देश के लोगों के लिए एक संजीवनी है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मोदी जी की सरकार ने अपने कम कार्यकाल में यह एक बहुत बड़ा काम किया है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं एक आखिरी लाइन कहना चाहूंगी। मैं एक बात यह बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार चाहती है कि सबको घर मिले, सबको आवास मिले, सबको सम्मान मिले और अब एक लाइन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूं।

*"अगर तूने सोची है किश्तियां डुबोने की,*
*तो हमने भी ठानी है आशियाना बनाने की।"*

यह मोदी सरकार का संकल्प है। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister to reply the discussion. Yes, Dr. K. Keshava Rao.

DR. K. KESHAVA RAO: I would like to thank the Government for conferring Bharat Ratna to Shri P.V. Narasimha Rao.

MR. CHAIRMAN: The House must collectively thank them. The House must collectively thank you. It is a good sentiment.

DR. K. KESHAVA RAO: I think nobody would object. We are thanking the Government for conferring Bharat Ratna to Shri P.V. Narasimha Rao and to Dr. M. S. Swaminathan also. He was my benchmate in this House. So, we thank the Government. Their contribution to the country is well-known to you, I need not repeat it. Hon. Finance Minister is a part of Shri P.V. Narasimha Rao's family. She used to go there as a couple. I remember this because Shri P.V. Narasimha Rao used to refer to them. Sir, I again, thank the Government for that.

**श्री प्रमोद तिवारी** (राजस्थान): सर, नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को और डा. स्वामीनाथन जी को, तीनों को 'भारत रत्न' दिया गया है, इसका पूरी कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, समर्थन करती है।

MR. CHAIRMAN: Dr. Keshava, let me indicate to you, when Narasimha Raoji was the hon. Prime Minister, I got a call one day...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I want to....

MR. CHAIRMAN: Dr. Thambidurai, please sit down. I got a call from the PMO. I used to make an effort to meet him frequently, but it used to fructify every 3-4 months. Then he said, 'You are a senior advocate. I want to associate you in my legal cell.' He was the President of the Congress Party also. I said, 'Hon. Prime Minister, any assignment is good enough.' I was part of the Congress Party. He made me in-charge of the legal cell. There were a number of occasions and you would recollect that when I got the message from the tweet of the hon. Prime Minister about the three of them, I reacted and indicated this, 'I am so glad that you have spoken about it and these are celebratory moments when the entire House must speak in one voice.'

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I was the Chairman of the Shri P. V. Narasimha Rao Centenary Celebrations Committee. That is why I wanted to go on record.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Mr. Chairman, Sir, thank you very much. We have had a Short Duration Discussion, but I think quite a lot of Members, many of them, have given us their valuable inputs on what they think of the White Paper and its contents. Sir, giving a very brief introduction to my speech, to my reply, not really getting into too much of a detail which is there in the White Paper itself because it is laid in both the Houses and I have given a fairly elaborate reply in the Lok Sabha and also fairly elaborate opening statement there, I would still get into some details but not too many. I understand the delay or the time that we need to conserve because we have one more discussion to take place. Sir, there is a need for me to just explain the economy in 2014, which we inherited, for a moment. It may suit the Members of the Opposition, at least some parties, particularly the Congress, to say that 'we had left the economy in prime shape, our growth rate was this per capita' and I can always have several Members from our side who speak. After all you inherited a good economy from Atal Behari Vajpayeeji's time and maybe in your first five years, you tried benefiting the people with that good economy, but subsequently and unfortunately, after the global financial crisis it was thorough mismanagement. All this can be said. Both sides can argue over them, but the fact is, these are already well analysed, well written about and they are out there in the public. It is not just for me to say it. We certainly say it because when we got the economy in 2014, when we inherited the economy and soon after that, a year later probably, hon. Prime Minister himself went public to say, it may not be the best time for me to get this out, he didn't at that time think whether he is going to come up with something later, but clearly the intention of why a white paper was not brought out was clearly stated by the Prime Minister himself. It would have certainly damaged the confidence the Indian citizens

had in our own country, in its institutions, in the strength of its economy, in the strength of the institutions which have to serve the economy and so on. So, he didn't want to shatter the confidence of the people. After all, they blessed him to come and serve the country. We all saw him evocatively bowing his head at the entrance of the Parliament saying he had come here as a servant of the people. 'I have come here to serve the country.' There is no good crying afterwards saying, 'Oh, the economy is really bad. I have come here, but I am sorry...' That wouldn't have been in the spirit of the things. So, he very clearly said, 'I am sorry, there is a lot of suggestion, but I am not doing it in the national interest because if I put it all threadbare, it will affect the confidence of the institutions, the investors and the people at large. So, that has been explained. Why now? It is because, as I said earlier, ten years of toiling to get economy back on its rail. Again, I will bring in this parallel. We have operated, in the last ten years, on two rails — rail which moves from one destination to another — one to correct the economy, remove the malpractices which had happened earlier, remove all those instruments which can be used as a weapon for ransacking. So, clear those archaic laws and rules, make Ease of Doing Business a primary concern and so on and so forth and looking at them equally. Sir, futuristic reforms were so important. I am sure, with all the respect that all of us have voiced — I was glad to hear — across the party lines, we have had such a wonderful farewell given to Dr. Manmohan Singh. I will join in it. But, equally, it is important, whether it is post-1991, or, ten years after 2004, the promised reforms of the 1991 itself were not complete at that time. Subsequently, when there was an opportunity again between 2004 and 2014, there were no reforms! It is one thing to continuously tell us 'What have you done? What have you done?' The two-track approach required for train to go forward — one is to remove malpractices and its impact on the economy and secondly not only carry forward those pending reforms waiting from 1991 but also even further to take the economy forward. So, that is the track we have laid for ourselves. And, there it goes, we have breached a stage where the economy can now say that we have reached the fifth position and we will reach third in the coming years. That is where I wanted to compare it. There is a proverb in Tamil. And, I am sure, every one of our language is rich in metaphors, idioms, rich in the local context and so on. There is a proverb in Tamil, *"Like a cloth on thorny bushes". There is a bunch of thorny bushes and, in that, a sari or cloth falls, how would you extricate that cloth from it? You will have to remove it from every thorn which pricks on the cloth. Then, to remove cloth without any damage, how much delicate and literally toil it

---

* English translation of the original speech delivered inTamil .

will be, so that cloth comes out clean, cloth comes out without getting torn and then put it on even clean. The economy was like a piece of cloth on a thorny bush. The bush was full of all those malpractices which have torn the economy. That is exactly how the economy was and there is no exaggeration. This is very evocative example or idiom I am using. But, actually, that was it. And, that is what we inherited. Otherwise, why would I say, "Like the cloth on thorny bushes"! What was the idiom/phrase the whole world was using for us? It was 'Fragile Five.' That is not what I am calling it. The world called you like that in 2014. The world called all of us. You were in an economy which was fragile! If you are fragile, what is the level of fragility? From the bottom, you are within the first five! If that is the हालात of the economy that the Prime Minister Modi and this Government inherited, and if we sit watching and wondering how to sort it out, what would have happened? Sir, straightaway we got into action. That is why the first Cabinet decision in 2014 was to form SIT to remove black-money and second was to form the Expenditure Reforms Commission under Dr. Bimal Jalan, so that all the profligate expenditure of the earlier Government could be rationalized, more systematic and answerable methods of doing governance put in place. Those were the first two decisions of this Government, clearly stating the intent with which we were getting on the job of cleaning economy and giving it a new lease of life. And, as a result, today, I am happy to say that we have reached where we have reached. At this stage, as an elected Government, we have every duty to inform the people of this country, to these two august Houses— Lok Sabha and the Rajya Sabha— where people's representatives are seated, so that they know the true picture of what it was then and what it is now and what effort it took for us to restore it. I would repeat that mind picture about our economy, 'a cloth on thorny bushes', and the way in which it had to be delicately removed from those thorny bushes, do legislation, do correction in the rules, also make sure that you are giving enough incentive where it has to go in the right place, savings by using technology; not one thing and not at one level, but across the board and at various levels, the economy had to be restored. So, today, when we are bringing a White Paper, it is because, as I said, we have brought the economy to a certain level and that level gives us a confidence that we are now not able to say within the next few years -- that is why the hon. Prime Minister keep saying -- but in our third term, surely, the economy will reach the third rank. And, this is not without a reason. And, above all, once again, why now? There should be a record for posterity so that we know what happens when the intent is not good and the transparency is not available in governance; what can happen to economy, and which should never be repeated. We need to have governance clean; we need to have governance that is accountable; and, not have

governance which is through extra constitutional bodies.

Sir, in the Lok Sabha, I had spent some time, explaining through various items -- which are parts of the White Paper, coal scam, how the banks went into a big mess and how that was brought back -- to explain all these things. I do not want to spend too much time going into one more or third more or fourth more in the list of items which we have mentioned in the White Paper. But, I am talking about the overall project implementation and the speed with which the schemes were implemented. And, that itself is one classic examples how everybody was going about their own in the Government and hon. Dr. Manmohan Singh was not able to get them all together to give that collective synergy. As a result, projects were delayed and were running into excess cost. And, despite already given that extra cost, the projects were still not getting completed. Our hon. Member from Assam spoke about how Bogibeel Bridge was sanctioned in 1997, if I know right, the hon. Member may correct me, and it took all these years to get completed. ...*(Interruptions)*... Yeah; yeah, I am conscious of that. I am conscious of that. For ten full years after that, you could not correct it. Now, don't point finger at Vajpayee*ji*. We have corrected it now. The Vajpayee Government could not do, you could have done that. It's alright to go on interrupting to satisfy your bosses. But, do have the patience to listen. ...*(Interruptions)*... Yeah; yeah, there will be some people reporting to your bosses. Right? You can correct me for every factual thing, which I am not saying right. But, don't go on weakening a person standing here, dare the guts out to speak to you, after you have been patiently heard out. ...*(Interruptions)*...

Aadhaar, Direct Benefit Transfer, Jan Aushadhi Kendra — they say all these are theirs, acknowledge them, they were the one to bring them in, and so on. Let me highlight just the Jan Aushadhi Kendra. Middle class, the poor, all of them benefit when the medicines are available for lesser price. Branded medicines have become so expensive that they can't afford that. The Jan Aushadhi Kendras were started in 2008. Who denies it? It's theirs. But, where was it. In 2008, they started; in 2014, only 80 *Jan Aushadhi Kendras* were established at that time, which is six years after it was launched. 80 centres only! They go on talking, Right to Food we established, we gave the Right to Information. *Arey,* Right for Medicine you also brought *na*. Why only 80 in six years? I just want to contrast this with what hon. Prime Minister Modi has done. Sir, the number of *Jan Aushadhi Kendras* reached 10,000 in December, 2023. And, common citizens are benefitting out of medicines which are available at affordable prices. More than 1,800 medicines are available in these Kendras and that is helping the poor and the middle class to obtain medicines at affordable prices. Sir, the Bogibeel bridge got completed in time; the hon. MP, Pabitra was speaking about

it. In all our Independent India's history, a second railway station in the North East happens when Prime Minister Modi comes in. After the first one, you forgot the North East. At least, you remember that Dr. Manmohan Singh himself was from Assam. उधर थोड़ा काम करते, वह भी नहीं किया। किसी के भी visits नहीं हुए। वहाँ जाते। I do not want to deride anybody. It is important to assimilate with people and join in their revelry also. सिर्फ उनके साथ गाना गाना और थोड़ा communal dancing में participate करना ही काफी नहीं है, आगे उधर काम भी करना चाहिए, उनके साथ मिल-जुल कर रहना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। वह तो नहीं हुआ। Sir, with regard to programme implementation, I would like to state here that the PM Modi personally monitors programmes and their progress through the video conference that he holds with the District level officers. They state how much progress is happening. If it is not happening, then, a Minister goes there and also follows it up. Up to 43rd edition of PRAGATI, 348 pending projects whose total cost is Rs.17.36 lakh crores have been reviewed; progress is happening; quickly, they are all coming to a conclusion. This kind of an effort never happened earlier. The biggest problem is this. A person who is so closely associated with infrastructure development openly said and I quote him: "The biggest problem of stalled projects appeared in the last two, three years of the UPA Government." This is a statement which reveals as to when it started showing up their inefficiency, lack of decision-making. In this period, infrastructure projects worth Rs.18 lakh crores were stalled. Whether it was through Ministry of Environment at that time or any other Ministry at that time, projects were stopped. So, this is about projects. The other one big example is the Eastern and Western Peripheral Expressway, which was again approved in 2006 and they had more than six years to complete it. It was never got done. And, it was in 2018 after the Prime Minister Modi comes in, that Expressways were completed. Project completion had come to a complete halt.

Sir, about inflation, repeatedly, there are figures thrown at us, inflation is this, inflation is that. I just want to highlight because Vajpayeeji's Government is also often mentioned; oh, Vajpayee was also there, that Government did not do anything. I want to tell you, Sir, inflation in the last year of Atal Bihari Vajpayeeji's Government, the NDA Government, was below four per cent. I am not very good in Hindi but I am tempted to use one saying. गुड़ को गोबर करना.., am I right? सर, गुड़ को गोबर करना, इनकी मास्टरी है। 2004 में जब एनडीए गवर्नमेंट में वाजपेयी जी ने 4 per cent below inflation के साथ आपके हाथ में सौंपा, तो आपने उसका क्या किया? गुड़ को गोबर कर दिया। Ill-targeted, reckless fiscal policy, ill-targeted subsidies, wasteful expenditure — all done for political gains. At the end of the day, they also had their turn of inflation. Targeting inflation is just not trying to contain inflation but supply-side measures also should be

done simultaneously so that lack of enough supplies will jack up price. You should contain that also. Now, we have a Group of Ministers which is monitoring every week what is the supply of tur dal, how much of pototoes are in the market. If the onions will have to be imported, we will import it. So, inflation-management also involves supply-side management. They had suffered from twin deficits. In 2013, 4.9 per cent was the fiscal deficit and 4.8 per cent was the current account deficit. So, they continuously lived with this. The priority was not that. And I am not saying all this. The most respected Dr. Manmohan Singh, in 2013, in AICC Session in Jaipur said, "Handling inflation is a shortcoming of the UPA Government." Dr. Manmohan Singh, not anywhere else, in AICC Session, not anywhere in some corner of the country, in Jaipur, says, "Handling inflation is a shortcoming of the UPA Governemnt." इसके बाद भी inflation के बारे में बार-बार यह कहा जाता है कि आपने क्या किया, हमने अच्छा किया। जब डा. मनमोहन सिंह जी ही कह रहे हैं, "Inflation management is a shortcoming of UPA Government." सर, वे खुद कह रहे हैं। So, average inflation under UPA, that is, between 2004 and 2014, was 8.2 per cent; average retail inflation during UPA-2, which is 2009-14, was over 10 per cent; double digit. Sir, double-digit inflation occurred nine times from January, 2012 to April, 2014. Nine times, it went beyond 10 per cent, और आप हमें inflation management के ऊपर ज्ञान देते रहते हैं। So, on the economic pain which the poor people had to face, please introspect before you accuse us.

Sir, what are we doing to contain inflation? We are strengthening buffer stock, making sure that key food items are kept in the buffer and released to the market every now and then, open market operations, easing out on imports whether of pulses or edible oil. Somebody did refer to Bharat Aata, Bharat Dal. Yes, we had to make sure that we purchased it wholesale, pack them in containers or bags which are saleable in Mother Dairy or NAFED or some Markfed kind of institutions. Therefore, when we did this, Bharat Atta at 27.50 rupees per kg, we have already sold 2.37 lakh metric tones as of 28th January, 2024, which means, the subsidized, easily-available Atta now is available for the common man in different places, and they noticed it and they bought and benefited from it. We have taken measures, and, as a result, subsidized Bharat Dal at 60 rupees per kg bag and 55 rupees per kg if it is 30-kg bag, 2.97 lakh metric tones, as of 31st January, has already been sold, meaning, poor people have already taken it from these various outlets. Onions are available at 25 rupees per kg, and, for that, 3.96 lakh metric tones have been already sold by 3rd February, 2024. Only recently, we have started Bharat Rice, being sold at 29 rupees per kg. So, I think, even in the Question Hour, Sir, I have gone into detail about how inflation is being managed. I don't want to elaborate on it. Much has been said also in the White Paper.

3.00 **P.M.**

Sir, there is just one more thing. Very senior Member, respected Shri K.C. Venugopal, raised a lot of issues. I just want to highlight some information, which some other people also talked about - Government jobs. I want to highlight that. The unemployment rate for Graduates has declined from 17.2 per cent in 2017-18 to 13.4 per cent in 2022-23. Overall unemployment rates, including everybody, declined from 5.8 per cent in 2018-19 to 3.2 per cent in 2022-23. So, it is coming down. The PLI Scheme also witnessed over Rs. 1.07 lakh crore of investment leading to production worth Rs. 8.7 lakh crore. Employment generation through that is about seven lakh; seven lakh individuals benefited from that. The yearly net payroll additions to the EPFO -- till some time ago the Minister was here -- more than tripled, from 61 lakh to 129 lakh, in 2022-23. Someone raised a question about Government jobs in particular. As many as 8,82,191 Central Government vacancies have been filled up -- I think it was Shri Tiruchi Siva who raised it; he is not here now -- in the last nine years as compared to just six lakhs vacancies that were filled up between 2004 to 2013. Regional Recruitment Boards gave Government jobs to 4,30,592 youth between 2014 and 2023. Government launched the *Rozgar Mela* in October, 2022 as a result of which today 6.32 lakh people have already got appointment letters in their hands. Ten lakh Central Government jobs have been given through that.

Sir, whenever we talk of inflation, there is this comparison between 'our period' and 'your period'. I have already, sort of, established that. One important fact is that despite collapse in crude oil prices in the second half of financial year 2009-10, 2010-11 and 2011-12, inflation was running in double digits. Crude oil prices were coming down, but that benefit was not being passed on to the common public. That is their policy. What is Prime Minister Modi's policy, Sir? Crude oil prices were at one level. When they started coming down, twice, once before Deepawali in 2021 and in 2022 again, we reduced the rates of excise. As a result, the pump price of fuel came down. So, the passing on to the common citizens is a very important criterion, which UPA never followed.

Sir, specifically, there were questions about EDs being used and weaponised and CBI being weaponised. I want to remind them of a few instances. There are several instances, but there is this one instance of how CBI was misused against an honest officer, SBI Chairman, Shri R.K.Talwar. He was an honest person who was heading the bank, but because he refused to give loan to one of their favourites, recommended by the 'first family', CBI went to his house and he was compelled to resign from the post of Chairman, SBI. That is weaponising. That was weaponising

CBI, nothing else. Here, when we have given independence to ED and they go searching, the accusation is, 'They do it only with Opposition Leaders.' I want to say, first of all, whether through CBI or ED, where the money laundering element comes, they want the money laundering to happen so that through the backdoor they can benefit out of it. So, ED and CBI did not follow on PMLA cases because that was important for them, they wanted the operation to keep going on. If it is stopped using PMLA, money will not come to them in the form of kickbacks. So, ED was made to remain dormant. CBI did not pursue PMLA cases; the data proves it. During their time, the number of prosecution complaints filed was 102 by ED, whereas when we have given them independence to contain black-money and contain money laundering, the number of cases now filed is 1,200. The number of restitutions, the amount that is restituted, which is taken away from the wrongdoer and given to banks and institutions, during their time, was nil. They did not restitute even one rupee from the wrongdoer to the bank or to anybody else, whereas the actual restitution during our period is Rs.16,333.02 crore, which has come to banks. Similarly, red corner notice and extradition has not been done during their time. Everything was nil. What we have done is to issue red corner notice on 24 people and orders have already been passed to extradite Vijaya Mallya, Nirav Modi and Sanjay Bhandari, all of whom were benefited through loans during their period. During their period, they gave loans and these people ran away from the country. They did not take any action. When we came to power, we had to send notice, fight the case and the orders for extraditing them have already been issued. I can't see K.C. Venugopal*ji* here, but I will still respond. You tell me one scheme that you have brought compared to ours, except RTE, RTI, NFSA. ...*(Interruptions)*... I want to highlight the facts. I am immensely grateful to our Member from Uttar Pradesh, Shri Brij Lal. He spoke to tell what exactly the mindset is.

MR. CHAIRMAN: He is a policeman.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Who is he?

MR. CHAIRMAN: He is a former DGP.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Better to be careful then! But, still, he spoke total truth. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What I meant was that DGPs have expertise on account of their training to know the mindset.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: He actually nailed the point so effectively. If we start looking at governance only from the point of view of entitlement, and not empowerment, you can always quote saying, Right to Food, Right to Education. It is all right. You did it; very well. I appreciate that. How many Acts have you brought in the name of right to something? Brij Lal*ji* has highlighted where that empowerment should have happened but it has happened under Modi; it did not happen earlier. What are they? He recited from 1947 how a *dalit* leader went to the then Pakistan, East and West Pakistan, and was made Law Minister. He came back and realised that *dalits* don't get empowered. This whole farce can be dispelled and to dispel it, you need a leader like Prime Minister, Modi. From 1947 till today, that approach of empowering *dalits* had not happened and empowering tribals hadn't happened. I am giving that example based on what Brij Lal*ji* highlighted. Five of the sacred sites of Dr. Ambedkar have been established and are flourishing under Prime Modi's time. They could contribute to Dr. B.R. Ambedkar only in one way. They feared people who would overshadow the 'first family', whether it was Dr.B.R. Ambedkar or former leader Charan Singh*ji* or Shyama Prasad Mukherjee*ji*. They make sure that such leaders, like Karpuri Thakurji, whom they perceive as being a threat to the 'first family', are undermined. They make them lose elections. They bring them to insignificance, and when somebody else gives them the recognition, gives them the due honour, they cannot digest it. That is their story. I am thankful to our hon. Member, Shri Brij Lal, to have brought that point back. Today, a woman tribal leader from Odisha is occupying the highest position as the hon. President of India, and that is because the hon. Prime Minister Modiji has given her the due honour. The birthday of Birsa Mundaji, who is *bhagwan* for the tribals, has been declared as the day of *samman* of all the tribals. Why could they not do it during their time? It is so because they believed only in keeping them as vote bank by just giving them few crumbs on the philosophy, 'You remain there, but give me vote'. That is the story. The hon. Prime Minister Modiji does not believe in that approach. He believes in empowering them, honouring them and that is the similar treatment and recognition which has been given to the *Sahibzaade,* the two young children of Guru Gobind Singhji, who gave their lives to protect this country. So, the approach is to empower people and not to keep them under your thumb because you want their votes by throwing few crumbs. No; that is the approach with which they were working and when they are asked to tell about one signature project that they had brought, they say that they had brought Right to Education, Right to Food and everything else. But, even while doing that, the so-called Right to Food Act, they did one thing here. Internationally, they did things to undermine that Act here. If you gave the Right to Food here, how did you go

to Bali in 2013 and give away the right of doing MSP-based procurement from farmers, keeping a buffer stock and releasing it through the PDS? You gave it all away by signing the Bali Declaration in Indonesia in 2013 and, here you come and tell that you have given the Right to Food! From 2017, if only that Bali Declaration were to be implemented, we would not be able to procure even one grain of rice from the farmers today. We would not be able to have ration shops today. We could not have given foodgrains from our buffer stock for the poor today. So, on the one side, they come and give Right to Food here, but on the other side, on the international platform, they go and sell away India's right to protect its farmers and protect its poor. So, this is the hypocrisy, and, therefore, if you are going to ask me as to what our signature contribution is, at least, we have honestly made sure that the poor get free foodgrains; they get houses; they get water in their houses; they get electricity; they get cooking gas. All this has been done under Prime Minister Modi.

Sir, I don't want to further take more time. There is just one important issue on the not so glamorous side of the reforms because most of us look at the glamorous side. There are some works which have been done, which have resulted in good amount of money being saved. Otherwise, pilferages happen and because of the pilferages, the Government was short of revenue. Now that we save it, we are able to do more projects for the poor. I did say that the Expenditure Reforms Committee was formed and as a result, the Budget cycle also was changed. As we used to present Budget at the end of February, the State Governments, which used to present their Budgets in the month of February, did not have the details of the Centre's Budget and, as a result, they were presenting something and trying to re-adjust. That got corrected because we started presenting the Budget on 1st February. The States are now able to get an idea of what is coming to them and plan for themselves. That is one. Secondly, by keeping the difference of Plan and non-Plan expenditure, they were constantly playing with the discretionary allotments, which is what the Planning Commission earlier used to do with all the State Governments. Such distinction is not even appropriate as non-Plan Expenditure includes maintenance of defence system, social security, pensions, insurance and even subsidy for the poor. We have shifted the focus to holistic allocation with bifurcation on revenue and capital expenditure. These changes have resulted in States feeling lot more empowered to plan their Budget. Also, Sir, Treasury Single Account is a system that we brought in, which influences how money goes to States for their schemes 'just-in-time'. As resources are borrowed to finance the Government's development agenda, the 'just-in-time' release helps in saving interest cost and fostering transparency. Let me clearly say. Treasury Single Account system, which we brought, has given an estimated savings

of Rs. 10,000 crores and that is being used for bigger schemes and for helping the poor. The Single Nodal System, another reform, and, glamorous, has given an estimated savings of Rs. 10,592 crores, again all these are going for *gareeb kalyan.*

Sir, this is my last point. "Oh, after demonetisation, all MSMEs have got wiped out, K.C. Venugopal ji said so". He was feeling very concerned. All of us feel concerned about MSMEs. He said, because of that, all MSMEs were struggling and many died. But I want to say here, Sir, as on 4th December, 2023, as per the Udyam Registration portal, the total number of MSMEs registered in the country is 3.16 crores, including informal micro enterprises which are in the Assist platform. In early January, as per the Udyam Registration portal, the total number of women-owned MSMEs was 1.17 crores. So, MSMEs are getting registered even newly.

Share of MSMEs in all-India exports during the year 2022-23 was 44 per cent. Do you think, it could happen in 2022-23 if MSMEs got wiped out post-demonetisation? Forty-four per cent of all-India exports are happening through MSMEs! So, they should do some more home work rather than making general observations which are getting disproved each time data is thrown at them. Sir, let me mention the efforts that we take. During the Covid itself, under Emergency Credit Line Guarantee Schemes (ECLGS), Rs. 5 lakh crore were extended for businesses, which were used by a lot of MSMEs. Let me tell you with a great sense of pride that even as we come to the end of that period, many of them have honoured their own loans, returned and serviced the interests, and, this guarantee is not going to be used by most of those loans which were given. Sir, Rs. 50,000 crore equity infusion through MSMEs Self Reliant India Fund has happened. We have done that for MSMEs. No global tender in this country for procurement can happen up to Rs. 200 crores as they have to be reserved for MSME. No global tenders!

Similarly, we launched an online portal 'CHAMPIONS' in June, 2020 to cover many aspects of e-governance so that they can be made easy. On the point of inclusion, when we think of MSMEs, we think of only manufacturing but what we have done is that we have brought in small traders on to this. As such, the retail and wholesale traders are also now recognized as MSMEs and they can get all the benefits. Non-tax benefits have been extended for three years in case of an upward change in status of MSME. We rolled out the 'Raising and Accelerating MSME Performance Scheme' with an outlay of Rs. 6,000 crores over five years. Lastly, Sir, the Udyam Assist platform was launched in 2023 to bring informal micro enterprises under the formal ambit to avail priority sector lending. It has also been done. So, MSMEs can now take the money which is coming under the priority sector lending umbrella. Lastly, I was a bit appalled...

MR. CHAIRMAN: Madam, this is the second 'lastly'.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Did I say one 'lastly'? I am sorry, Sir. I will correct myself. Sir, 'Who made Charan Singh P.M.', was the observation made by K.C. Venugopal ji. People make PMs. I hope the Congress Party is not living in that thing that they make the PM, they throw the PM; they bring in the PM and they reject the PM. No! The people have rejected the Congress. You are well aware of the politics of that time. Indira-Congress decided to extend support to Chaudhary Charan Singh ji, who took oath as the Prime Minister on 28th July, 1979. Within 24 days, he resigns. Why? It was because Indira Gandhi's Congress withdrew support. Chaudhary Charan Singh ji said that he resigned because he was not ready to be blackmailed into withdrawing cases against Indira Gandhi, the cases which were put on her post-Emergency. Indira Gandhi ji wanted Charan Singh ji to withdraw certain cases against her relating to the excesses committed during Emergency, and he refused. While resigning, Charan Singh ji said, and I quote, "The country would not have forgiven us if we had, for the sake of remaining in office, agreed to withdraw prosecutions against persons responsible for atrocities during Emergency." That is the honour with which that person left from there. Chaudhray Charan Singh ji had to leave because he did not think he should yield to that blackmailing. So, it was the Congress Party which brought down Chaudhray Charan Singh ji in 1979. Good that K.C. Venugopal ji brought that up. It is alright for them to now say, 'It is alright you go away!' to his grandson. But the fact remains that they had no respect for Chaudhary Charan Singh ji. This is the way they blackmailed. An honourable man that he was, he said, "No, I am not falling into this". And he went away. Similarly, today, I am grateful that our Government has honoured P.V. Narasimha Rao ji. Many things can be said. 1991 reforms, if he was not the Prime Minister at that time, even an economist, Dr. Manmohan Singh, could not have performed what he did as a Government. The Congress Party did not even have the gratefulness to recognise him even after his death. The pictures, the video of the Party's headquarters office gate closing, even as his corpse was going, will bring tears to anybody's eyes. A person sacrifices and serves a party, but because of prejudice, you ignored him even after his death. That is the gratefulness this party has shown! And I don't need to say that it is the party whose Prime Ministers gave themselves the Bharat Ratna. Nehru ji, Indira ji, all gave themselves the Bharat Ratna. They didn't bother about others, and they, certainly, didn't bother about Dr. B.R. Ambedkar, who they constantly kept defeating in political fields. They didn't give the Bharat Ratna to him. Therefore, Sir, this party

should not shed crocodile tears or, should not say, for the records sake, "We welcome Bharat Ratna being given to P.V. Narasimha Rao ji, to Chaudhary Charan Singh ji and so on. They have proven when they were alive how torturous their lives were, how they tortured them. All that is very clear, and it will go on the records of the Parliament as to how, when they were alive, they tortured them, insulted them, and now, when a different party, when Prime Minister Modi, gives them Bharat Ratna, they are not even able to gulp the fact. Thank you very much.

---

## OBSERVATIONS BY THE CHAIR - *Contd.*

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्यगण, आज का दिन मेरे लिए अत्यंत पीड़ा का रहा है। मैं आपसे और मन से संरक्षण चाहता हूं। मर्यादित आचरण में रहना, ऐसे पल आते हैं, मुश्किल हो जाता है। पूर्ण सद्भाव के साथ सदन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, दुखी और आहत मन से मैं आपके समक्ष चिंतन का एक विषय रखता हूं। यह सदन पूरे देश का प्रतीक है। इस सदन में जो भी आचरण होता है, उसका चिंतन होता है, अध्ययन होता है, लोगों के मन में प्रसन्नता होती है और लोगों का मन दुखी भी होता है। ईमानदारी के प्रतीक, उत्कर्ष आचरण के धनी, किसान और गरीब के हितकारी भारत के पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देना, स्वाभाविक रूप से सभी के लिए एक उत्सव का विषय होना चाहिए था। बाकी चार महानुभावों को दिया, यह भी अत्यंत उत्सव का विषय होना चाहिए था। न समय को हम देख सकते हैं, न यह कह सकते हैं कि क्यों दिया। मैं यह भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज दिन भर में बहुत से लोगों ने मुझे सूचित भी किया है। इस सदन की गरिमा का आहत होना और मेरा इस आसन पर विराजमान होना, आज मेरे लिए दुखदायी रहा। मैं मानकर चलता हूं कि इस सदन का हर सदस्य भारत के इस महान सपूत को जो भारत रत्न दिया गया, उस पर गर्व महसूस करता है। उनके पोते को, उनके लिखित अनुरोध पर सदन में कुछ समय देना स्वाभाविक था। चौधरी चरण सिंह किसी परिवार तक सीमित नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह अपने उस परिवार तक भी सीमित नहीं हैं, वे पूरे देश के थे। जब यह मुद्दा उठा और जो आचरण मैंने और आप सब ने देखा, वह अप्रत्याशित था, अपमानजनक था, पीड़ादायक था, हमारी गरिमा के विपरीत था। कुछ लोगों का आचरण इतना छोटा था कि मैं शर्मसार हो गया। मेरे मन में कई विचार आए और मेरे मन में एक विचार तुरंत पद त्याग का भी आया। ...(**व्यवधान**)... मैं बताता हूं, कृषक पुत्र होने के नाते ...(**व्यवधान**)... नहीं, सेंसिटिव नहीं ...(**व्यवधान**)... केशव जी, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...केशव जी, मैं सेंसिटिव नहीं हूं। मैंने जीवन में कभी भी, आप मुझसे कई बार मिल चुके हैं और आपकी हर रीज़नेबल बात को मैंने देखा है। फिर मुझे बताया गया कि मैं इस पद पर पदासीन नहीं हूं, मैं इस पद पर पदासीन हूं by virtue of being the Vice-President of the country; I am *ex officio* Chairman, उस पद की वजह से मैं यहां हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में बहुत कठिन पल आए हैं। मैंने अपने जवान बेटे को खोया है, लोगों ने सहानुभूति दी है, पर आज की पीड़ा, जब